



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 39] नई दिल्ली, सितम्बर 21—सितम्बर 27, 2008, शनिवार/भाद्र 30—आश्विन 5, 1930

No. 39] NEW DELHI, SEPTEMBER 21—SEPTEMBER 27, 2008, SATURDAY/BHADRA 30—ASHWINA 5, 1930

इस भाग में छिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृष्ठक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2008

का.आ. 2666—राष्ट्रपति, दिनांक 24-07-2008 (अपरह्न)
से श्री एम. चन्द्रशेखरन का भारत के उच्चतम न्यायालय में भारत के
अपर महासालिसिटर के पद से त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

[फा. सं. 18 (8)/2007-न्यायिक]

एम. ए. खान यूसुफी, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 8th September, 2008

S.O. 2666.—The President is pleased to accept the
resignation of Shri M. Chandrasekharan, as Additional
Solicitor General of India in the Supreme Court of India
w.e.f. 24-07-2008 (AN).

[F. No. 18(8)/2007-Judl.]

M. A. KHAN YUSUFI, Jt. Secy. & Legal Adviser

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2008

का.आ. 2667—केंद्रीय सरकार दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
(1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, सर्वश्री राजीव पाटिल, मेघश्याम के. कोचरेकर और
संदीप काशीनाथ शिंदे, अधिवक्ताओं को, मुंबई स्थित उच्च न्यायालय में
भारत संघ या केंद्रीय सरकार के किसी विभाग या कार्यालय द्वारा या
उसके विरुद्ध सभी दंडिक मामलों का, जिनके अंतर्गत दंडिक रिट
याचिकाएं, दंडिक अपीलें, दंडिक पुनरीक्षण, दंडिक निर्देश और दंडिक
आवेदन भी हैं, संचालन करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में इस
अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की और अवधि के लिए
या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इस शर्त के अधीन
रखते हुए अपर लोक अभियोजक नियुक्त करती है कि सर्वश्री राजीव
पाटिल, मेघश्याम के. कोचरेकर और संदीप काशीनाथ शिंदे, अधिवक्ता
अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान ऊपर निर्दिष्ट किसी दंडिक मामले
में भारत संघ या केंद्रीय सरकार के किसी विभाग या कार्यालय के विरुद्ध
मुंबई स्थित उच्च न्यायालय में उपसंज्ञात नहीं होंगे।

[फा. सं. 23 (2)/2008-न्या.]

एम. ए. खान यूसुफी, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

New Delhi, the 16th September, 2008

S.O. 2667.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints S/Shri Rajiv Patil, Meghashyam K. Kocharekar and Sandeep Kashinath Shinde, Advocates as Additional Public Prosecutor for the purpose of conducting all criminal cases including criminal writ petitions, criminal appeals, criminal revisions, criminal references and criminal applications by or against the Union of India or any Department or Office of the Central Government, in the High Court of Judicature at Mumbai, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for a period of one year or until further orders, whichever is earlier, subject to the condition that S/Shri Rajiv Patil, Meghashyam K. Kocharekar and Sandeep Kashinath Shinde, Advocates, shall not appear against the Union of India or any Department or Office of the Central Government in any criminal case referred to above, in the High Court of Judicature at Mumbai during the period of his appointment.

[F. No. 23 (2)/2008-Judl.]

M. A. KHAN YUSUFI, Jt. Secy. & Legal Adviser

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2008

का.आ. 2668.—केंद्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभाव पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 के साथ पठित रॉड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री जी. एन. श्रीनिवासन, अधिवक्ता को मुंबई स्थित उच्च न्यायालय के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो तथा अन्य अभिकरणों के सभी दौड़िक मामलों का संचालन करने के प्रयोजन के लिए तुरंत प्रभाव से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इस शर्त के अधीन रहते हुए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है कि श्री जी.एन. श्रीनिवासन, अधिवक्ता, अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान ऊपर निर्दिष्ट किसी दौड़िक मामले में भारत संघ या केंद्रीय सरकार के किसी विभाग या कार्यालय के विरुद्ध मुंबई स्थित उच्च न्यायालय में उपसंज्ञत नहीं होंगे।

[फा. सं. 23 (2)/2008 न्या.]

एम. ए. खान युसुफी, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

New Delhi, the 16th September, 2008

S.O. 2668.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby appoints of Shri G. N. Srinivasan, Advocate as Special Public Prosecutor, for the purpose of conducting all criminal cases of Directorate of Enforcement, Central Bureau of Investigation, Narcotics Control Bureau and other agencies before the High Court of Bombay at Mumbai with immediate effect for a period of one-year or until further

orders, whichever is earlier, subject to the condition that Shri G. N. Srinivasan, Advocate shall not appear against the Union of India or any Department or Office of the Central Government in any criminal case referred to above in the High Court of Judicature at Mumbai during the period of his appointment.

[F. No. 23 (2)/2008-Judl.]

M. A. KHAN YUSUFI, Jt. Secy. & Legal Adviser

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2008

का.आ. 2669.—केंद्रीय सरकार रॉड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुंबई स्थित उच्च न्यायालय में भारत संघ या केंद्रीय सरकार के किसी विभाग या कार्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध सभी दौड़िक मामलों का, जिनके अंतर्गत दौड़िक रिट याचिकाएं, दौड़िक अपीलें, दौड़िक पुनरीक्षण, दौड़िक निर्देश और दौड़िक आवेदन भी हैं, संचालन करने के प्रयोजन के लिए, श्री जितेंद्र आर. सोलंकी, अधिवक्ता की अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति की अवधि को तुरंत प्रभाव से एक वर्ष की और अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इस शर्त के अधीन रहते हुए विस्तारित करती है कि श्री जितेंद्र आर. सोलंकी, अधिवक्ता, एक वर्ष की विस्तारित अवधि के दौरान ऊपर निर्दिष्ट किसी दौड़िक मामले में भारत संघ या केंद्रीय सरकार के किसी विभाग या कार्यालय के विरुद्ध मुंबई स्थित उच्च न्यायालय में उपसंज्ञत नहीं होंगे।

[फा. सं. 23 (2)/2008-न्या.]

एम. ए. खान युसुफी, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

New Delhi, the 16th September, 2008

S.O. 2669.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby extends the term of appointment of Shri Jitendra R. Solanki, Advocate as Additional Public Prosecutor for the purpose of conducting all criminal cases including criminal writ petitions, criminal appeals, criminal revisions, criminal references and criminal applications by or against the Union of India or any Department or Office of the Central Government, in the High Court of Judicature at Mumbai, with immediate effect for a further period of one-year or until further orders, whichever is earlier, subject to the condition that Shri Jitendra R. Solanki, Advocate, shall not appear against the Union of India or any Department or Office of the Central Government in any criminal case referred to above, in the High Court of Judicature at Mumbai during the extended period of one year.

[F. No. 23 (2)/2008-Judl.]

M. A. KHAN YUSUFI, Jt. Secy. & Legal Adviser

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन प्रजालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2008

का. आ. 2670.—केंद्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की

धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, गृह (पुलिस), खण्ड-3 की अधिसूचना सं. 2843 पी/6-पी-3-2008-15 (59) पी/08 दिनांक 4 अगस्त, 2008 द्वारा प्राप्त उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति से पुलिस थाना छर्ता, जिला अलीगढ़ में भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं. 45), की धारा 489-बी, 489-सी, 124-ए एवं 420 के तहत दर्ज अपराध सं. 357 एवं 358/2007 के अधीन अपराधों और उपर्युक्त अपराधों में से एक अथवा अधिक से संबंधित अथवा संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षडयंत्र तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अथवा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किन्हीं अन्य अपराधों के अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य पर करती है।

[सं. 228/69/2008-ए.पी.डी.-II]

चंद्र प्रकाश, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 15th September, 2008

S.O. 2670.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Uttar Pradesh, Home (Police) Section-3 vide Notification No. 2843P/6-P-3-2008-15 (59) P/08 dated 4th August, 2008, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttar Pradesh for investigation of Case Crime Nos. 357 and 358/2007 under sections 489-B, 489-C, 124-A and 420 of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) registered at Police Station Chharrha, District Aligarh and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the offence mentioned above any other offence or offences committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[No. 228/69/2008-AVD-II]

CHANDRA PRAKASH, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2008

का. आ. 2671.—केंद्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, गृह (पुलिस), खण्ड-3 की अधिसूचना सं. 3259-पी(2)/6-पी-3-2008-15 (61) पी/2008 दिनांक 8 अगस्त, 2008 द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं. 45), की धारा 489-बी और 489-सी, के तहत पुलिस थाना जीआरपी लखनऊ में दर्ज (1) मामला सं. 252/08, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं. 45) की धारा 489-बी और 489-सी, के तहत पुलिस थाना डूमरियागंज, सिद्धार्थनगर में दर्ज (2) मामला सं. 557/08 एवं भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का

अधिनियम सं. 45) की धारा 409, 489-बी और 489-सी के तहत और (3) मामला सं. 571/08 और उपर्युक्त अपराधों से संबंधित अथवा संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षडयंत्र तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में अथवा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध अथवा अपराधों का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य पर करती है।

[सं. 228/72/2008-ए.पी.डी.-II]

चंद्र प्रकाश, अवर सचिव

New Delhi, the 15th September, 2008

S.O. 2671.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Uttar Pradesh, Home (Police) Section-3 vide Notification No. 3259P (2)/VI-P-3-2008-15 (61) P/2008 dated 8th August, 2008, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttar Pradesh for investigation of (1) Case Crime No. 252/08 under sections 489-B and 489-C, of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) registered at Police Station GRP Lucknow, (2) Case Crime No. 557/08 under sections 489-B and 489-C of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) registered at Police Station Dumariaganj, Siddharthnagar and (3) Case Crime No. 571/08 under sections 409, 489-B and 489-C of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) registered at Police Station Dumariaganj, Siddharthnagar and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the offence mentioned above and any other offence or offences committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[No. 228/72/2008-AVD-II]

CHANDRA PRAKASH, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2008

का. आ. 2672.—केंद्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, गृह (पुलिस), खण्ड-3 की अधिसूचना सं. 2936-पी(2)/6-पी-3-2008-15 (59) पी/2008 दिनांक 12 अगस्त, 2008, द्वारा प्राप्त उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति से पुलिस थाना कोतवाली नगर, जिला बिजनौर में भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं. 45), की धारा 489-बी एवं 489-सी, के तहत दर्ज अपराध सं. 1281/2008 के अधीन अपराधों और उपर्युक्त अपराधों में से एक अथवा अधिक से संबंधित अथवा संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षडयंत्र तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अथवा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किन्हीं अन्य अपराधों के अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की

शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य पर करती है।

[सं. 228/74/2008-एवोडी-II]

चंद्र प्रकाश, अवर सचिव

New Delhi, the 15th September, 2008

S.O. 2672.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Uttar Pradesh, Home (Police) Section vide Notification No. 2936P(2)/VI-P-3-2008-15 (59) P/2008 dated 12th August, 2008, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttar Pradesh for investigation of Case Crime No. 1281/2008 under sections 489-B and 489-C, of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) registered at Police Station, Anandpur City, District Bijnor and attempts, abettments and conspiracies in relation to or in connection with the offences mentioned above and any other offence or offences committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[No. 228/74/2008-AVD-II]

CHANDRA PRAKASH, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2008

का. आ. 2673.—केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, गृह (राजनैतिक) विभाग की अधिसूचना सं. 896-पो.एस. दिनांक 12 अगस्त, 2008 द्वारा राज्य पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति से राजस्व आसूचना निदेशालय, कोलकाता द्वारा दिनांक 10-06-2008 को मोहम्मद समोसद्दीन और उसकी पत्नी अंजुमन समीर, जो बेंगलोर-पेट्रापोल भू-सोमा के साथ से होते हुए बांग्लादेश से भारत में दाखिल हुए उनके पास दो बैग और दो दाम्नी बैग जो इनको डाका के एक धाकूब नाम के व्यक्ति ने सौंपा था तथा जिनको से जाकर हावड़ा में कुमार नाम के व्यक्ति के सुर्द किया जाना था, के कब्जे से 38,38,500 रुपये के जाली भारतीय मुद्रा नोट जब्त किए गए, के विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली में कानूनी कार्रवाई के लिए प्राप्त राजस्व आसूचना निदेशालय, कोलकाता जोनल यूनिट-8, हां ची मिन, सरानी, कोलकाता-700001 की शिकायत सं. डीआरआईएक सं. 92/कोल/2008 (पी)/983 दिनांक 17-06-2008 के तहत भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं. 45) की धारा 489-बी, 489-सी संपत्ति धारा 120-बी के अधीन उपरोक्त अपराधों से संबंधित उनकी धोखाधड़ी और किसी अन्य लोकसेवक या व्यक्ति तथा उपर्युक्त अपराधों से संबंधित अथवा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध अथवा अपराधों का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की

शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल राज्य पर करती है।

[सं. 228/76/2008-एवोडी-II]

चंद्र प्रकाश, अवर सचिव

New Delhi, the 15th September, 2008

S.O. 2673.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of West Bengal, Home (Political) Department vide Notification No. 896-P.S. dated 12th August 2008, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of West Bengal for investigation of the case relating to seizure of Fake Indian Currency Notes, of Rs. 38, 38, 500 effected on 10-6-2008 by the Directorate of Revenue Intelligence, Kolkata from the possession of one Mohammad Samiruddin and his wife Anzuman Samir who entered India from Bangladesh via Benapole-Petrapole land border alongwith two bags and two trolley bags which had been handed over by one Yakub of Dhaka and carried by them and meant to be delivered to one Kumar at Howrah, against whom Central Bureau of Investigation, New Delhi received complaint for initiating legal action under Indian Penal Code from the Directorate of Revenue Intelligence, Kolkata, Zonal Unit 8, Ho Chi Minh Sarani, Kolkata-700001 vide Complaint No. DRI F, No. 92/KOL/2008 (P)/983 dated 17-6-2008, for their fraudulent acts and any other public servants or persons, in relation to said offences under Sections 489-B, 489-C read with 120 B of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) and any other offences committed in the course of the same transaction or emerging out of the same facts or facts in relation to aforesaid seizure.

[No. 228/76/2008-AVD-II]

CHANDRA PRAKASH, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2008

का.आ. 2674.—केंद्रीय सरकार दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एस. कल्याणसुंदरम, अधिवक्ता को विशेष जज का न्यायालय, चेन्नई में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (के.अ.ब्यूरो) द्वारा संस्थित मामलों में अभियोजन तथा अपील/पुनरीक्षण न्यायालय (यों) में अपील, पुनरीक्षण और किसी अन्य न्यायालय में इससे संबंधित अथवा प्रासंगिक किसी अन्य विषय का संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. 225/41/2007-एवोडी-II]

चंद्र प्रकाश, अवर सचिव

New Delhi, the 16th September, 2008

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2008

S.O. 2674.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri S. Kalyanasundaram, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting prosecution in the cases instituted by the Delhi Special Police Establishment (CBI), in the Special Judge Court, Chennai and appeals, revisions in the appellate or revisional court(s) and any other matter concerned therewith or incidental thereto in any other court.

[No. 225/41/2007-AVD-II]

CHANDRA PRAKASH, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2008

का.आ. 2675.—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अधिवक्ताओं को पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता में विचारण न्यायालयों में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (के.अ. ब्यूरो) द्वारा सौस्थित और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उन्हें सौंपे गए मामलों के अभियोजन और विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में इन मामलों से उद्भूत अपीलों/पुनरीक्षणों अथवा अन्य विषयों का संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है :—

सर्वश्री

1. डी.सी. सरकार,
2. समीर रंजन भट्टाचार्य,
3. बिस्वजीत पुसिलाल ।

[सं. 225/30/2007-एवीडी-II]

चंद्र प्रकाश, अवर सचिव

New Delhi, the 16th September, 2008

S.O. 2675.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints following Advocates as Special Public Prosecutor for conducting prosecution of cases instituted by the Delhi Special Police Establishment (CBI) in the State of West Bengal at Kolkata as entrusted to them by the Central Bureau of Investigation in the trial courts and appeals/revisions or other matters arising out of these cases in revisional or appellate courts established by law :

1. Shri D.C. Sarkar,
2. Shri Samir Ranjan, Bhattacharya,
3. Shri Biswajit Pusilal.

[No. 225/30/2007-AVD-II]

CHANDRA PRAKASH, Under Secy.

का.आ. 2676.—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अधिवक्ताओं को केरल राज्य, कोचीन में विचारण न्यायालयों में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (के.अ. ब्यूरो) द्वारा सौस्थित और उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सौंपे गए मामलों के अभियोजन और विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में इन मामलों से उद्भूत अपीलों/पुनरीक्षणों अथवा अन्य विषयों का संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है :—

सर्वश्री

1. सी.पी. उदयभानु,
2. के.डी. बाबु
3. अजीत कुमार ।

[सं. 225/31/2007-एवीडी-II]

चंद्र प्रकाश, अवर सचिव

New Delhi, the 17th September, 2008

S.O. 2676.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints following Advocates as Special Public Prosecutor for conducting prosecution of cases instituted by the Delhi Special Police Establishment (CBI) in the State of Kerala at Cochin as entrusted to them by the Central Bureau of Investigation in the trial courts and appeals/revisions or other matter arising out of these cases in revisional or appellate courts established by law :

S/Shri

1. C.P. Udayabhanu,
2. K. D. Babu,
3. Ajit Kumar.

[No. 225/31/2007-AVD-II]

CHANDRA PRAKASH, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2008

का.आ. 2677.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में राजस्व विभाग के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के निम्नलिखित कार्यालय को जिनके 80% कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क,
48, प्रशासनिक क्षेत्र,
अरेरा हिल्स,
भोपाल ।

[फा. सं. 11012/1/2008-हिन्दी-2]

मधु शर्मा, निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 9th September, 2008

S.O. 2677.—In pursuance of Sub Rule 4 of rule 10 of the Official Language (Use of Official Purpose of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following office under the Central Board of Excise & Customs, Department of Revenue, the 80% staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Office of the Commissioner of Central Excise & Customs, 48, Administrative Area, Aera Hills, Bhopal.

[F. No. 11012/1/2008-Hindi-2]

MADHU SHARMA, Director (O.L.)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2008

का.आ. 2678- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ दिनांक 1-4-2008 से संगठन कैंसर इंस्टीट्यूट (डब्ल्यू आई ए), चेन्नई को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आंशिक रूप से अनुसंधान कार्यकलापों में संलग्न 'अन्य संस्था' की श्रेणी में अनुमोदित किया गया है, नामतः—

- (i) अनुमोदित संगठन को प्रदत्त राशि का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा;
- (ii) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों अथवा इसके नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को जारी रखेगा;
- (iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में अलग खाता बही रखेगा जिसमें अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाई गई हो, उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से ऐसी खाता-बही की लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आय की विवरणों प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत् सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट पामने में

क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा ।

- (iv) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत् सत्यापित विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा ।

2. केन्द्र सरकार यह अनुमोदन वापिस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन :—

- (क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में उल्लिखित अलग लेखा बही नहीं रखेगा; अथवा
- (ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा; अथवा
- (ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान एवं प्रयुक्त राशि का अपना विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा; अथवा
- (घ) अपना अनुसंधान कार्यकलाप करना बंद कर देगा अथवा इसके अनुसंधान कार्य-कलाप को जायज नहीं पाया जाएगा; अथवा
- (ङ) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के उपबंधों के अनुरूप नहीं होगा तथा उनका पालन नहीं करेगा ।

[अधिसूचना सं. 92/2008/फा. सं. 203/141/2007-आ.क.नि.-11]

रेनु जोहरी, निदेशक (आ.क.नि.-11)

(Central Board of Direct Taxes)

New Delhi, the 18th September, 2008

S.O.2678.—It is hereby notified for general information that the organization Cancer Institute (WIA), Chennai has been approved by the Central Government for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 (said Act), read with Rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962 (said Rules), with effect from 1-4-2008 in the category of 'other Institution', partly engaged in research activities subject to the following conditions, namely:

- (i) The sums paid to the approved organization shall be utilized for scientific research;
- (ii) The approved organization shall carry out scientific research through its faculty members or its enrolled students;
- (iii) The approved organization shall maintain separate books of account in respect of the sums received by it for scientific research, reflect therein the amounts used for carrying out research, get such books audited by an

accountant as defined in the explanation to sub-section (2) of Section 288 of the said Act and furnish the report of such audit duly signed and verified by such accountant to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax having jurisdiction over the case, by the due date of furnishing the return of income under sub-section (1) of Section 139 of the said Act;

- (iv) The approved organization shall maintain a separate statement of donations received and amounts applied for scientific research and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of audit referred to above.

2. The Central Government shall withdraw the approval if the approved organization :—

- (a) fails to maintain separate books of accounts referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or
- (b) fails to furnish its audit report referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or
- (c) fails to furnish its statement of the donations received and sums applied for scientific research referred to in sub-paragraph (iv) of paragraph 1; or
- (d) ceases to carry on its research activities or its research activities are not found to be genuine; or
- (e) ceases to conform to and comply with the provisions of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the said Act read with rules 5C and 5E of the said Rules.

[Notification No. 92/2008/F. No. 203/141/2007/ITA-II]

RENU JAUHRI, Director (ITA-II)

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2008

क्र.आ. 2679.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा, घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 के उपबंध, आईसीआईसीआई बैंक पर, उसके द्वारा जून 2007 में 10.88 करोड़ इक्विटी शेयरों के सार्वजनिक निर्गम और 5.00 करोड़ अमेरिकी जमा रसीदों (एडीआर) के मामले में, लागू नहीं होंगे

[फा. सं. 13/6/2007-बीओए]

डॉ. डी. माहेश्वरी, अवर सचिव

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 18th September, 2008

S.O. 2679.—In exercise of the powers conferred by Section 53 (1) of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government, on the recommendations of Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 13 of the said Act, shall not apply to ICICI Bank Ltd. in case of the public issue of 10.88 crore equity shares and 5.00 crore American Deposit Receipts (ADRs) by the Bank in June, 2007.

[F. No. 13/6/2007-BOA]

D. D. MAHESHWARI, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2008

क्र.आ. 2680.—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 33) की धारा 6 के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में नियुक्त करती है :-

- (i) आवास/शहरी विकास विभाग के मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार,
जयपुर ।
- (ii) आवास/शहरी विकास विभाग के मुख्य सचिव,
तमिलनाडु सरकार,
चेन्नई ।

[फा. सं. 7/1/2008-बीओ-1]

जी. बी. सिंह, उप सचिव

New Delhi, the 19th September, 2008

S.O. 2680.—In exercise of the powers conferred by clause (f) of Section 6 of the National Housing Bank Act, (1987) (53 of 1987), the Central Government hereby appoints the following persons to be the Directors on the Board of Directors of National Housing Bank (NHB) for a period of three years with effect from the date of issue of this notification :—

- (i) Principal Secretary of the Housing/
Urban Development Department,
Government of Rajasthan,
Jaipur.
- (ii) Principal Secretary of the Housing/
Urban Development Department,
Government of Tamil Nadu,
Chennai.

[F. No. 7/1/2008-B.O.-1]

G. B. SINGH, Dy. Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2008

का.आ. 2681.—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), राजभाषा नियम 1976 (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुसरण में राइट्स लिमिटेड, गुडगांव के निम्नलिखित कार्यालय को जहाँ 80% से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्वारा अधिसूचित करता है :-

राइट्स लिमिटेड, परियोजना कार्यालय,
बीएच 741/742, चौथी मंजिल, टावर नं. 7,
इंटरनेशनल इन्फोटेक पार्क,
वाशी रेलवे स्टेशन कॉम्प्लेक्स, वाशी,
नवी मुंबई-400 703

[सं. हिंदी-2008/रा.भा. 1/12/1]

संसार चंद, निदेशक, (राजभाषा), रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAY

(Railway Board)

New Delhi, the 19th September, 2008

S.O. 2681.—Ministry of Railways (Railway Board), in pursuance of Sub Rule (2) and (4) of Rule 10 of the Official Languages (use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, hereby, notify the following office of RITES Limited, Gurgaon, where 80% or more Officers/Employees have acquired the working knowledge of Hindi :-

Rites Limited, Project Office,
VAT 741/742, 4th Floor, Tower No. 7
International Infotech Park,
Vashi Railway Station Complex, Vashi,
Navi Mumbai-400 703

[No. Hindi-2008/O.L. 1/12/1]

SANSAR CHAND, Director (O.L.), Railway Board

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2008

का.आ. 2682.—इस मंत्रालय की दिनांक 31 मई, 2007 को समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में और चलचित्र (प्रमाणन) नियमावली, 1983 के नियम 7 और 8 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से दो वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, श्री के. राजशेखर प्रसाद को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के हैदराबाद सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा.सं. 809/11/2007-एफ (सी)]

संगीता सिंह, निदेशक (फिल्म)

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 10th September, 2008

S.O. 2682.—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated 31st May, 2007 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) read with rules 7 and 8 of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983 the Central Government is pleased to appoint Shri K. Rajasekhara Prasad as a member of the Hyderabad advisory panel of the Central Board of Film Certification with immediate effect for a period of two years or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 809/11/2007-F (C)]

SANGEETA SINGH, Director (Films)

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2008

का.आ. 2683.—इस मंत्रालय की दिनांक 5 फरवरी, 2008 को समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में और चलचित्र (प्रमाणन) नियमावली, 1983 के नियम 3 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से तीन वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, श्रीमती उर्मिला रूंगटा, 64, जुहु गोल्ड मिस्ट, गुलमोहर रोड, जे वी पी डी स्कीम, फोर्ट, मुम्बई-400049 को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा.सं. 809/11/2007-एफ (सी)]

संगीता सिंह, निदेशक (फिल्म)

New Delhi, the 10th September, 2008

S.O. 2683.—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated 5th February, 2008 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) read with rule 3 of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983 the Central Government is pleased to appoint Smt. Urmila Rungta, 64, Zuhu Gold Mist, Gulmohar Road, JVPD Scheme, Fort, Mumbai-400049 as a member of the Central Board of Film Certification with immediate effect for a period of three years and until further orders.

[F. No. 809/11/2007-F (C)]

SANGEETA SINGH, Director (Films)

विदेश मंत्रालय

(सी. पी. बी. प्रचार)

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2008

का.आ. 2684.—राजनयिक बीम्बली अधिकारी (प्रथम एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 113) के 2 के अंक (क) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार एतद्वारा भारत का प्रथम कोसलभास,

फ़ॉसिस्को में श्री बी.एन. दत्ता, सहायक को 1-9-2008 से सहायक कौंसली अधिकारी का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है।

[सं. टी-4330/01/2006]

प्रीतम लाल, अवर सचिव (कौंसुलर)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(C.P.V. Division)

New Delhi, the 1st September, 2008

S.O. 2684.—In pursuance of the clause (ii) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948, the Central Government hereby authorize Shri B.N. Dutta, Assistant to perform the duties of Assistant Consular Officer in the Consulate General of India, San Francisco.

[No. T. 4330/1/2006]

PRITAM LAL, Under Secy. (Consular)

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2008

का.आ. 2685.—राजनयिक कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) खण्ड 2 के अंक (क) के अनुसार में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत का प्रधान कौंसलावास, सफाई में श्री सूर्योदय सिंह रावत, सहायक को 11-9-2008 से सहायक कौंसली अधिकारी का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है।

[सं. टी-4330/01/2006]

प्रीतम लाल, अवर सचिव (कौंसुलर)

New Delhi, the 11th September, 2008

S.O. 2685.—In pursuance of the clause (ii) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948, the Central Government hereby authorize Shri Suryodaya Singh Rawat, Assistant to perform the duties of Assistant Consular Officer in the Consulate General of India, Shanghai.

[No. T. 4330/1/2006]

PRITAM LAL, Under Secy. (Consular)

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2008

का.आ. 2686.—राजनयिक कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम 1948 (1948 का 41वां) खण्ड 2 के अंक (क) के अनुसार में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत का राजदूतावास, लिस्बन में श्री एर्नेस्ट अलेक्सांडर एडम्स, सहायक को 17-9-2008 से सहायक कौंसली अधिकारी का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है।

[सं. टी-4330/01/2006]

प्रीतम लाल, अवर सचिव (कौंसुलर)

New Delhi, the 17th September, 2008

S.O. 2686.—In pursuance of the clause (ii) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948, the Central Government hereby authorize Shri Ernest Alexander Adams, Assistant to

perform the duties of Assistant Consular Officer in the Embassy of India, Lisbon.

[No. T. 4330/1/2006]

PRITAM LAL, Under Secy. (Consular)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

[आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग]

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का. आ. 2687.—केंद्रीय सरकार राजभाषा “संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग” नियम 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित संस्थानों जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारियों ने हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है :-

- | | |
|---|-----------|
| 1. केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान | लखनऊ |
| 2. केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान | भुवनेश्वर |
| 3. क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद) | झाँसी |
| 4. क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद) | बंगलूर |
| 5. क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान आयुर्वेद | जम्मू |
| 6. क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान आयुर्वेद | विजयवाड़ा |
| 7. क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान | पटना |

[सं. ई. 11018(2)/2/2003-पा. वि. प. (रा. भा.)]

शिव बंसत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

[Department of Ayurved, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha, Homoeopathy (Ayush)]

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2687.—In pursuance of sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Language “Use for official purpose of the Union” Rule, 1976 the Central Govt. hereby notifies the following offices under the administrative control of Department of AYUSH, Ministry of Health & Family Welfare whereof 80% staff have acquired the working knowledge of Hindi:

- | | |
|--|------------|
| 1. Central Ayurved Research Institute | Lucknow |
| 2. Central Ayurved Research Institute | Bhubneswar |
| 3. Regional Research Institute (Ayurved) | Jhansi |
| 4. Regional Research Institute (Ayurved) | Bangalore |
| 5. Regional Research Institute (Ayurved) | Jammu |
| 6. Regional Research Institute (Ayurved) | Vijaywada |
| 7. Regional Research Institute of Unani Medicine | Patna |

[No. E-11018(2)/2/2003-I.S.M.(O.L.)]

SHIV BASANT, Jr. Secy.

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2008

क्र. आ. 2688.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1)(ख) के उपबंध के अनुसरण में डा. ओ. पी. तिवारी, आचार्य महात्मा गांधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर, सदस्य, काय चिकित्सा विभाग, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पांच वर्षों के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के सदस्य के रूप में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जाता है :-

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का. आ. 138 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में शीर्षक "धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित" के अंतर्गत क्रम संख्या 33 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"33. डा. ओ. पी. तिवारी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय"

आचार्य,

महात्मा गांधी स्मारक

चिकित्सा महाविद्यालय,

इंदौर

[संख्या जी-11013/1/007-एम ई(नैति-1)]

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

(Department of Health)

New Delhi, the 15th September, 2008

S.O. 2688.—Whereas in pursuance of the provision of sub-section (1) (b) of Section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) Dr. O.P. Tiwari, Professor, Mahatma Gandhi Memorial Medical College, Indore, a member of the faculty of Medicine, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore has been elected by the Council of Devi Ahilya Vishwavidyalaya to be a member of the Medical Council of India for five years with effect from date of issue of this notification.

Now, therefore, in pursuance of the provision of the sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India in the then Ministry of Health number S.O. 138 dated the 9th January, 1960, namely:-

In the said Notification, under the heading, "Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3", against serial number 33, the following entries shall be substituted, namely:-

"33. Dr. O.P. Tiwari, Devi Ahilya Vishwavidyalaya"
Professor
Mahatma Gandhi Memorial
Medical College, Indore

[No. V.11013/1/2007-ME(P-I)]

S. K. GUPTA, Under Secy.

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2008

क्र. आ. 2689.— इस मंत्रालय की दिनांक 25 जून, 2008 की अधिसूचना सं. यू. 12012/379/2006-एमई (पी-II) के आंशिक संशोधन में शीर्षक "पंजीकरण हेतु संक्षेपण" (स्तम्भ-3) में के अन्तर्गत शर्तों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

"यह एक मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी यदि यह मणिपाल विश्वविद्यालय (पूर्व में मणिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी के रूप में जाना जाने वाला) (भम विश्वविद्यालय) मणिपाल, कर्नाटक द्वारा कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल, कर्नाटक एवं कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मंगलूर, कर्नाटक में प्रशिक्षित छात्रों के संबंध में वर्ष 2009 से अथवा उससे पहले प्रदान की गई हो।"

अधिसूचना की शेष विषय-वस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

[सं. यू. 12012/379/2006-एमई (पी-II)]

एन. बारिक, अवर सचिव

(Department of Health and Family Welfare)

Corrigendum

New Delhi, the 23rd September, 2008

S.O. 2689.—In partial modification to this Ministry's Notification No.U.12012/379/2006-ME(P-II) dated 25th June 2008, under the heading "Abbreviation for Registration" [in column (3)], the conditions mentioned there in may be replaced by the following namely:-

"This shall be a recognized medical qualification when granted by Manipal University (Formerly known as Manipal Academy of Higher Education) (Deemed University) Manipal, Karnataka when granted in or before the year 2009 in respect of students trained at Kasturba Medical College, Mainpal, Karnataka and Kasturba Medical College, Mangalore, Karnataka."

Remaining contents of the Notification shall remain unchanged.

[No. U.12012/379/2006-ME(P-II)]

N. BARIK, Under Secy.

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2008

क्र. आ. 2690.—राष्ट्रीय नौवहन-बोर्ड-नियमावली, 1960 के नियम 4 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 44) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके और इस मंत्रालय की दिनांक 1-9-2008 के समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, 1 सितम्बर, 2008 से दो वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के निम्नलिखित छः सदस्यों के नाम अधिसूचित करती है :—

1. श्री एस. हाजरा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड ।
 2. श्री अतुल अग्रवाल, संयुक्त प्रबंध निदेशक, मर्केटर लाइन्स लि. ।
 3. श्री वाई. डी. खटाऊ, प्रबंध निदेशक, वरूण शिपिंग कं. लि. ।
 4. डॉ. शान्ति पटेल, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय नाविक संघ ।
 5. श्री एस. एस. खान, महासचिव, भारतीय समुद्री संघ ।
 6. डॉ. एम. के. पांथे, उपाध्यक्ष, फॉर्वाड सीमेन्स यूनियन ऑफ इंडिया ।
- शेष छः सदस्यों के नाम बाद में अधिसूचित कर दिए जाएंगे ।

(फा. सं. एस एस-18011/1/2008-एस एल)

ए. के. तिवारी, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

New Delhi, the 15th September, 2008

S. O. 2690. —In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with Rule 4 of the National Shipping Board Rules, 1960 and in continuation of this Ministry's Notification of even number dated 1-9-2008, the Central Government hereby notifies the names of the following six Members of the National Shipping Board for a period of two years with effect from 1st September, 2008—

1. Shri S. Hazara, Chairman & Managing Director, Shipping Corporation of India Ltd.
2. Shri Atul Agarwal, Joint Managing Director, Mercator Lines Ltd.
3. Shri Y. D. Khatau, Managing Director, Varun Shipping Co. Ltd.
4. Dr. Shanti Patel, President, National Union of Seafarers of India.
5. Shri S. S. Khan, General Secretary, The Maritime Union of India.
6. Dr. M.K. Pandhe, Vice President, Forward Seamen's Union of India.

Names of the remaining six Members of the Board will be notified in due course.

(P. No. SS-18011/1/2008-SL.)

A. K. TEWARI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2008

क्र. आ. 2691.—राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड नियमावली, 1960 के नियम 4 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 44) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, 1 सितम्बर, 2008 से दो वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :—

1. कैप्टन पी. वी. के. मोहन, अध्यक्ष ।
2. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ।
3. संयुक्त सचिव (नौवहन), पोत परिवहन विभाग ।
4. संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग ।
5. नेवल स्टॉफ के उप मुख्य ।
6. नौवहन महानिदेशक ।
7. निदेशक, राष्ट्रीय समुद्रीय संस्थान, चेन्नई ।
8. अध्यक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ।
9. अध्यक्ष, एनौर पोर्ट लिमिटेड ।
10. प्रो. एन. एम. रामास्वामी, अध्यक्ष, प्रो. एन. एम. आर अनुसंधान एवं विकास, कोयंबटूर ।

शेष सदस्यों के नाम बाद में अधिसूचित कर दिए जाएंगे ।

(फा. सं. एस एस-18011/1/2008-एस एल)

ए. के. तिवारी, उप सचिव

New Delhi, the 18th September, 2008

S. O. 2691.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with Rule 4 of the National Shipping Board Rules, 1960, the Central Government hereby establishes the National Shipping Board for a period of two years with effect from 1st September, 2008 consisting of the following Members :—

1. Capt. P.V.K. Mohan, Chairman.
2. Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of Shipping, Road Transport & Highways.
3. Joint Secretary (Shipping), Department of Shipping.
4. Joint Secretary, Department of Commerce.

5. Deputy Chief of Naval Staff.
6. Director General of Shipping.
7. Director, National Maritime Academy, Chennai.
8. Chairman, Cochin Shipyard Limited.
9. Chairman, Mangalore Port Limited.
10. Prof. N. M. Rameswamy, Chairman, Prof. N.M.R. Foundation Research and Development, Coimbatore.

Names of the remaining Members of the Board will be notified in due course.

[F.No. SS-18011/1/2008-SL]

A. K. TEWARI, Dy. Secy.

कोयला पंत्रालय

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2008

का. अ. 1592, -केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला पंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1625, तारीख 28 अप्रैल, 2006 द्वारा जो भारत के राजपूताना भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 29 अप्रैल, 2006 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थापन में ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों के अर्जन करने की अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है :

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और महाराष्ट्र सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है, कि इससे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 254.15 हेक्टर (लगभग) या 628.03 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए ।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है, कि अनुसूची में वर्णित 254.15 हेक्टर (लगभग) या 628.03 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के समस्त अधिकार अर्जित किए जाते हैं ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. सी. -1 (ई) /III/जेजेएमआर/760-0508 तारीख 21 मई, 2008 का निर्देशन कलेक्टर, चंद्रपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1 कार्मिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता (पिन-700 001) के कार्यालय में या वेस्टन कोलफोल्ड्स लिमिटेड (राजस्व विभाग), कोल एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर-440 001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

अनुसूची

एकोणा- I ओपनकास्ट खंड

माजरी क्षेत्र

जिला चंद्रपुर (महाराष्ट्र)

(रेखांक सं. सी-1 (ई)/III/जेजेएमआर/760-0508 तारीख 21 मई, 2008)

समस्त अधिकार:

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पट्टेवारी सफिल संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणियाँ
1.	एकोणा	11	बरोरा	चंद्रपुर	50.11	भाग
2.	मार्दा	11	बरोरा	चंद्रपुर	40.65	भाग
3.	बनोजा	11	बरोरा	चंद्रपुर	18.60	भाग
4.	चरूर (खटी)	10	बरोरा	चंद्रपुर	144.79	भाग

कुल क्षेत्र : 254.15 हेक्टर (लगभग)

या

628.03 एकड़ (लगभग)

ग्राम एकोणा में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक:

87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 98/1, 98/2, 98/3, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 104/3, 105, 106, 107, 108, 109, 110/1, 110/2, 110/3, 111, 112, 113, 114, 115, 116/1, 116/2, सड़क (भाग)।

ग्राम मार्दा में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक:

132, 137, 138, 139, 140/1, 140/2, 140/3, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147/1, 147/2, 148/1, 148/2, 162, 163, सड़क (भाग)।

ग्राम बनोजा में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक:

134, 152, 153, 154, 155, 156, सड़क (भाग)।

ग्राम चरूर (खटी) में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक:

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/1, 76/2, 77, 78/1, 78/2, 79, 80, 81/1, 81/2, 81/3, 82, 83, 84, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 86/3, 464, 466/1, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5, 466/6, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492 सड़क (भाग)।

सीमा वर्णन:

क-ख: रेखा बिन्दु "क" से आरंभ होती है और प्लॉट संख्यांक 87, 89 की बाहरी सीमा के साथ-साथ ग्राम एकोणा से

होकर गुजरती है तथा ग्राम एकोणा और चरुर (खटी) की सम्मिलित सीमा को पार करती है और प्लॉट संख्या 86/1, की बाहरी सीमा के साथ जाती है और सड़क पार कर प्लॉट संख्यांक 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 46 की बाहरी सीमा के साथ जाती है और सड़क पार करती है, फिर प्लॉट संख्यांक 491, 492, 464, 466/5 की बाहरी सीमा के साथ जाती हुई बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख-ग: रेखा ग्राम चरुर (खटी) से होते हुए प्लॉट संख्यांक 466/5, 466/2, 467, 468, 469 की बाहरी सीमा के साथ जाते हुए सड़क पार करती है फिर प्लॉट संख्या 471 की बाहरी सीमा के साथ जाती हुई ग्राम चरुर (खटी) और वनोजा की सम्मिलित ग्राम सीमा को पार करती है तथा ग्राम वनोजा के प्लॉट संख्यांक 156, 152, 134, की बाहरी सीमा के साथ गुजरती है और सड़क पार करती है, फिर सड़क की बाहरी सीमा के साथ जाती हुई ग्राम माडा के प्लॉट संख्या 163 की बाहरी सीमा के साथ जाती हुई बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग-क: रेखा प्लॉट संख्यांक 163, 162, 147/1, 147/2, 148/2, 140/3, की बाहरी सीमा के साथ ग्राम माडा से होकर जाती है, सड़क पार करती है फिर प्लॉट संख्यांक 137, 132 की बाहरी सीमा के साथ जाती है और ग्राम माडा और एकोणा की सम्मिलित ग्राम सीमा को पार करती है, फिर प्लॉट संख्यांक 116/2, 116/1, 103/2, 103/1, 98/3, 98/1, 97, 92, 91, 87, की बाहरी सीमा के साथ गुजरती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[फा. संख्या. 43015/6/2005-पी.आर.आई.डब्ल्यू-1]

एम. शाहबुद्दीन, अवर सचिव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 22nd September, 2008

S.O. 2692—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S. O. 1625 dated the 28th April, 2006, issued under sub-section (1) of Section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part-II, Section-3 sub-section (ii), dated the 29th April, 2006, the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands and all rights in or over such lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And, whereas, the competent authority in pursuance of Section 8 of the said Act, has made his report to the Central Government;

And, whereas, the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Maharashtra, is satisfied that the lands measuring 254.15 hectares (approximately) or 628.03 acres (approximately) and all rights in or over such lands as described in the Schedule appended hereto, should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby declares that the land measuring 254.15 hectares (approximately) or 628.03 acres (approximately) and all rights in or over such lands as described in the Schedule are hereby acquired.

The plan bearing number C-1 (E)/III/JJMR/760-0508 dated the 21st May, 2008 of the area covered by this notification, may be inspected in the office of the Collector, Chandrapur (Maharashtra) or in the office of the Coal Controller, I, Council House Street, Kolkata (Pin 700 001) or in the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur - 440 001 (Maharashtra).

SCHEDULE

YEKONA - I OPENCAST BLOCK MAJRI AREA

DISTRICT - CHANDRAPUR (MAHARASHTRA)

(Plan number C-1 (E)/III/JJMR/760-0508 dated the 21st May, 2008).

All Rights

Sl. No.	Name of village	Patwari circle No.	Tahsil	District	Area in Hectares	Remarks
01	Yekona	11	Warora	Chandrapur	50.11	Part
02	Marda	11	Warora	Chandrapur	40.65	Part
03	Wanoja	11	Warora	Chandrapur	18.60	Part
04	Charur (Khati)	10	Warora	Chandrapur	144.79	Part

Total area: 254.15 hectares (approximately)
or 628.03 acres (approximately)

Plot numbers acquired in village Yekona :

87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 98/1, 98/2, 98/3, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 104/3, 105, 106, 107, 108, 109, 110/1, 110/2, 110/3, 111, 112, 113, 114, 115, 116/1, 116/2, Road (Part).

Plot numbers acquired in village Marda :

132, 137, 138, 139, 140/1, 140/2, 140/3, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147/1, 147/2, 148/1, 148/2, 162, 163, Road (Part).

Plot numbers acquired in village Wanoja :

134, 152, 153, 154, 155, 156, Road (Part).

Plot numbers acquired in village Charur (Khati) :

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/1, 76/2, 77, 78/1, 78/2, 79, 80, 81/1, 81/2, 81/3, 82, 83, 84, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 86/3, 464, 466/1, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5, 466/6, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, Road (Part).

Boundary description :

A-B: Line starts from point 'A' through village Yekona and passes along the outer boundary of plot numbers 87, 89, and crosses common village boundary of villages Yekona and Charur (Khati) then proceeds through village Charur (Khati) along the outer boundary of plot number 86/1, crosses road then proceeds along the outer boundary of plot numbers 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 46 and crosses road then proceeds along the outer boundary of plot numbers 491, 492, 464, 466/5 and meets at point 'B'.

B-C: Line passes through village Charur (Khati) along the outer boundary of plot numbers 466/5, 466/2, 467, 468, 469 crosses road then proceeds along the outer boundary of plot number 471, crosses common village boundary of villages Charur (Khati) and Wanoja, then proceeds through village Wanoja along the outer boundary of plot numbers 156, 152, 134, crosses road and proceeds along the outer boundary of road in village Wanoja, then proceeds through village Marda along the outer boundary of plot number 163 and meets at point 'C'.

C-D: Line passes through village Marda along with the outer boundary of plot numbers 163, 162, 147/1, 147/2, 148/2, 140/3, crosses road then proceeds along the outer boundary of plot numbers 137, 132, crosses common village boundary of villages Marda and Yekona then proceeds along the outer boundary of plot numbers 116/2, 116/1, 103/2, 103/1, 98/3, 98/1, 97, 92, 91, 87, and meets at starting point 'A'.

[F.No.43015/6/2005-PRW-I]
M. SHAHABUDEEN, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2008

का. आ. 2693- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कांयला अधिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कांयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है :

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का रेखांक सं. डी. जी./8736 तारीख 3 जुलाई, 2008 का निरीक्षण मुख्य महाप्रबंधक (गवेषण प्रभाग), सेन्दल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट गोंडवाना प्लेस, कॉक रोड, राँची या कोयला नियंत्रक, 1, कार्डमिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700 001 के कार्यालय में या जिला कलेक्टर रायगढ़, छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि में हितवद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर मुख्य महाप्रबंधक (गवेषण प्रभाग), सेन्दल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट गोंडवाना प्लेस, कॉक रोड, राँची को भेजेगें ।

अनुसूची

स्यांग साउथ ब्लॉक, मांद रायगढ़, कोयला क्षेत्र

जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़

रेखांक सं. डीजी/8736 तारीख 3 जुलाई, 2008

क्रम सं.	ग्राम	थाना/ तहसील	ग्रा. सं.	जिला	क्षेत्रफल एकड़ में	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	टिप्पणी
1.	स्यांग	कोरबा	524500	रायगढ़	1011	409	भाग
2.	डेगुरडीह	करताला	523500	रायगढ़	232	94	भाग
3.	शुटमा	कोरबा	43000	रायगढ़	346	140	भाग
4.	सीमकोडा	कोरबा	524400	रायगढ़	2545	1030	भाग
5.	एलोग	कोरबा		रायगढ़	22	9	
6.	वनक्षेत्र	कोरबा	-	रायगढ़	774	313	भाग
कुल					4930	1995	(लगभग) (लगभग)

सीमा विवरण

क-ख रेखा वन क्षेत्र में 'क' बिन्दु से आरंभ होती है और स्यांग ग्राम के मध्य भाग से गुजरती हुई 'ख' बिन्दु पर मिलती है ।

- ख-ग रेखा डेगुरदीह ग्राम के मध्य भाग से गुजरती हुई शुदमा गाँव के पश्चिमी भाग में 'ग' बिन्दु पर मिलती है।
- ग-घ रेखा सीमकेडा गाँव के दक्षिण पूर्वी भाग की ओर मुड़कर एलोग ग्राम के कोने पर बिन्दु 'घ' पर मिलती है।
- घ-ङ रेखा मुड़ती हुई जंगल की सीमा के कोने पर बिन्दु 'ङ' पर मिलती है।
- ङ-क रेखा वन से गुजरती है और वन के बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[फा. संख्या 43015/11/2008-पी.आर.आई.डब्ल्यू-1]

एम. शाहाबुद्दीन, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd September, 2008

S.O. 2693 —Whereas, it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands in the locality mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisitions and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein:

The plan number DG/8736 dated the 3rd July, 2008 of the area covered by this notification can be inspected at the office of Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata or at the office of the District Collector, Raigarh, Chhattisgarh.

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred in sub-section (7) of Section 13 of the said Act to the Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi within ninety days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE

SAYANG SOUTH BLOCK, MAND RAIGARH COALFIELD
DISTRICT RAIGARH, CHHATISGARH

Plan bearing number DG/8736 dated the 3rd July, 2008

Sl. No.	Vill.	Thana/ Tehsil	Vill. No.	District	Area in Acres	Area in Hectares	Remarks
1	SAYANG	KORBA	524500	RAIGARH	1011	409	Part
2	DEGURDIH	KARTALA	523500	RAIGARH	232	94	Part
3	SHUDMA	KORBA	43000	RAIGARH	346	140	Part
4	SIMKEDA	KORBA	524000	RAIGARH	2545	1030	Part
5	ELOG	KORBA		RAIGARH	22	9	
6	FOREST	KORBA		RAIGARH	774	313	Part
TOTAL					4930 (approximately)	1995 (approximately)	

BOUNDARY DESCRIPTION

- A-B The line start at point 'A' in the forest and passes through middle part of Sayang village and meets point 'B'.
- B-C The line passes through middle part of village Dengurdih and meets point 'C' in the western part of village Shudma.
- C-D The line turned towards South Eastern part of village Simkeda and meets point 'D' on the edge of village Elog.
- D-A The line turn and meet point 'E' at the edge of forest boundary.
- E-A The line passes through in the forest and meets point 'A' in the forest.

[F.No. 43015/11/2008-PRIW-1]
M. SHAHABUDEEN, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2008

का. आ. 2694—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वोक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का रेखांक सं. डी. जी./8737 तारीख 3 जुलाई, 08 का निरीक्षण मुख्य महाप्रबंधक (गवेषण प्रभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट गोंडवाना प्लेस, कान्के रोड, राँची या कोयला निर्यंत्रक, 1, कार्डोसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 के कार्यालय में या जिला कलेक्टर रायगढ़, छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर मुख्य महाप्रबंधक (गवेषण प्रभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट गोंडवाना प्लेस, कान्के रोड, राँची को भेजेंगे।

अनुसूची

चिरा नार्थ वेस्ट ब्लॉक, मांद रायगढ़ कोयला क्षेत्र

जिला—रायगढ़, छत्तीसगढ़

रेखांक सं. डीजी/8737 तारीख 3 जुलाई, 2008

क्रम सं.	ग्राम	थाना/ तहसील	ग्रा. सं.	जिला	क्षेत्रफल एकड़ में	क्षेत्रफल हेक्टर में	टिप्पणी
1.	एलोग	कोरबा		रायगढ़	327.35	132.47	भाग
2.	चिरा	कोरबा		रायगढ़	1259.81	509.84	भाग
3.	सुदमा	कोरबा	524300	रायगढ़	2529.54	1023.70	भाग
4.	टेंगरीमार	कोरबा		रायगढ़	902.70	365	भाग
5.	बोरो धर्मजयगढ़	कोरबा	321600	रायगढ़	486.07	196.70	भाग
6.	सीमाकेडा	कोरबा		रायगढ़	49.60	20.07	भाग
7.	वनक्षेत्र	कोरबा		रायगढ़	148.79	60.21	भाग
कुल					5703.86	2308.00	
					(लगभग)	(लगभग)	

सीमा विवरण

क-ख रेखा एलोग ग्राम के 'क' बिन्दु से शुरू होकर और चिरा के दक्षिण भाग, सुदमा ग्राम के मध्य भाग से गुजरती है।

ख-ग रेखा बोरो ग्राम के दक्षिण पश्चिमी भाग से गुजरती हुई वन क्षेत्र के 'ग' बिन्दु पर मिलती है।

ग-घ रेखा वन से गुजरती हुई सुदमा एवं चिरा ग्राम के मध्य भाग से पार होकर एलोग ग्राम के बिन्दु 'घ' पर मिलती है।

घ-क रेखा मुड़कर एलोग ग्राम के उत्तरी सिरे पर बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[फा. संख्या. 43015/12/2008-पी.आर.आई.डब्ल्यू-1]

एम. शहाबुद्दीन, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd September, 2008

S.O 2694—whereas, it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands in the locality mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisitions and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein;

The plan number DG/8737 dated the 3rd July, 2008 of the area covered by this notification can be inspected at the office of Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata or at the office of the District Collector, Raigarh, Chattisgarh.

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of Section 13 of the said Act to the Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi within ninety days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE.

CHIRA NORTH WEST BLOCK, MAND RAIGARH COALFIELD, DISTRICT RAIGARH, CHHATTISGARH

Plan number DG/8737 dated the 3rd July 2008

Sl. No.	Vill.	Thana/ Tehsil	Vill. E No	District	Area in Acres	Area in Hectares	Remarks
1	Elog	Korba		Raigarh	327.35	132.47	Part
2	Chira	Korba		Raigarh	1259.81	509.84	Part
3	Sudma	Korba	524300	Raigarh	2529.54	1023.70	Part
4	Tengrimar	Korba		Raigarh	902.70	365	Part
5	Boro	Korba	321600	Raigarh	486.07	196.70	Part
	Dharamjagar						
6	Simkeda	Korba		Raigarh	49.60	20.07	Part
7	Forest	Korba		Raigarh	148.79	60.21	Part
TOTAL					5703.86	2308.00	
					(approx-	(approx-	
					imately)	imately)	

BOUNDARY DESCRIPTION

A-B The line start at point 'A' in village Elog and passes through southern part of Chira, middle part Shudma village.

- B-C The line passes through south-western part of village Boro and meets point 'c' in the forest area.
- C-D The line crossed the forest, middle part of Shudma and Chira village and meets point 'D' in the village Elog.
- D-A The line turns and meets point 'A' at the Northern edge of the village Elog.

[File No. 43015/12/2008-PRIW-I]

M. SHAHABUDEEN, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2008

क्रा. आ. 2695.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपायध्व अनुसूची में बलिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का रेखांक सं. डी. जी./08735 तारीख 3 जुलाई, 08 का निरीक्षण मुख्य महा-प्रबंधक (गवेषणा प्रभाग), सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, राँची या कोयला नियंत्रक का कार्यालय, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता के कार्यालय में या जिला कलेक्टर रायगढ़, छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि में हितवद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर मुख्य महाप्रबंधक (गवेषणा प्रभाग), सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, राँची को भेजेंगे।

अनुसूची

स्यांग नार्थ खण्ड, मंद रायगढ़ कोयला क्षेत्र
जिला—रायगढ़, छत्तीसगढ़

क्रम सं.	ग्राम तहसील	थाना/ ग्र. सं.	जिला	क्षेत्रफल एकड़	क्षेत्रफल हेक्टर	टिप्पणियाँ
				में	में	
1.	चिरहुट	कोरबा	रायगढ़	573.34	232.84	भाग
2.	स्यांग	कोरबा	रायगढ़	1349.09	545.97	भाग
3.	सरसा रेखा	कोरबा	रायगढ़	1071.33	433.56	भाग
4.	होपुरहीह कालासा	कोरबा	रायगढ़	4.40	0.03	भाग
5.	वनक्षेत्र	कोरबा+ धर्मजगढ़ क्षेत्र	रायगढ़	704.29	285.00	भाग
कुल				3706.45 (लगभग)	1500.00 (लगभग)	

सीमा विवरण

- क-ख रेखा (साइन) जंगल के 'क' बिन्दु से शुरू होती है और चिरहुट ग्राम के मध्य भाग से गुजरती हुई सरसा देवा ग्राम में 'ख' बिन्दु पर मिलती है।
- ख-ग रेखा (साइन) सरसा देवा ग्राम के पश्चिमी भाग से गुजरती है और जंगल में 'ग' बिन्दु पर मिलती है।
- ग-घ रेखा सरसा देवा और स्यांग ग्राम को पार करके घूमती है और कोसरी जंगल के किनारे पर बिन्दु 'घ' पर मिलती है।
- घ-क रेखा बिन्दु 'क' पर जंगल में ही वापस मिल जाती है।

[फा. संख्या. 43015/10/2008-पीआरआईडब्ल्यू-1]

एम. शहाबुद्दीन, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd September, 2008

S.O. 2695.—whereas, it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands in the locality mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisitions and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein;

The plan bearing number DG/8735 dated the 3rd July, 2008 of the area covered by this notification can be inspected at the office of Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata or at the office of the District Collector, Raigarh, Chattisgarh.

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred in sub-section (7) of Section 13 of the said Act to the Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi within ninety days from the date of publication of this notification.

SCHEDULE

SAYANG NORTH BLOCK, MAND RAIGARH
COALFIELD DISTRICT RAIGARH,
CHHATISGARH

Plan bearing number DG/8735 dated the 3rd July 2008

Sl. No.	Vill.	Thana/Tehsil	Vill No.	District	Area in Acres	Area in Hectares	Remarks
1	Chirhut	Korba	524400	Raigarh	573.34	232.84	Part
2	Sayang	Korba	524600	Raigarh	1349.09	545.97	Part
3	Sarsadewa	Korba	525200	Raigarh	1071.33	433.56	Part
4	Degandih	Korba/Katada	523500	Raigarh	4.40	0.03	Part
5	Forest	Korba+ Dharmajgarh		Raigarh	704.29	285.00	Part
TOTAL					3706.45 (Approximately)	1500.00 (Approximately)	

BOUNDARY DESCRIPTION

- A-B The line start at point 'A' in the forest and passes through middle part of Chirhut village and meets point 'B' in the village Sarsadeva.
- B-C The line passes through western part of village Sarsadeva and meets point 'C' in the forest.
- C-D The line turned and the forest Sarsadeva and Sayang village crossed and meets point 'D' on the edge of forest Kosiari.
- D-A The line turn and meet point 'A' again in the forest.
- [File No.43015/10/2008-PRW-I]
M. SHAHABUDEEN, Under Secy.

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards Established	No. & Year of Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Establishment
(1)	(2)	(3)	(4)
1	IS 6773:2008 Sodium silicate for use in foundries- Specification (second revision)	IS 6773:1978	31 July, 2008

Copy of the this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref. MTD 14/1-31]

Dr. (Mrs.) SNEH BHATIA, Scientist 'F' & Head (Met Engg.)

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का.आ. 2697.- भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि अनुसूची में दिये गये मानक (को) में संशोधन किया गया/किये गये है :

अनुसूची

क्रम संख्या	संशोधित भारतीय मानक (को) की सं. वर्ष और शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आईएस 1536:2001 जल, गैस एवं मल जल के लिए अपकेंद्रों दलर्था (स्पन) लोहे के दाब पाइप-विशिष्ट (चौथा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 28, दिसम्बर 2003	28 अगस्त, 2008
2	आईएस 1536:2001 जल, गैस एवं मल जल के लिए अपकेंद्रों दलर्था (स्पन) लोहे के दाब पाइप-विशिष्ट (चौथा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1, जुलाई 2008	28 अगस्त, 2008

इन संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयंबटूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ: एपटीडी (4/1-31)]

डा. (श्रीमति) स्नेह भट्टा, वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख (एपटीडी)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2696.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each:

मुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में विक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ: एमटीडी 6/टी-10]

डा. (श्रीमति) स्नेह भाटला, वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख (एमटीडी)
New Delhi, the 4th September, 2008

S. O. 2697.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each:

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standard(s) amendment(s)	No. & Year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 1536:2001 Centrifugally cast (spun) iron pressure pipes for water, gas and sewage (fourth revision)	Amendment No.2 December 2003	28 August 2008
2.	IS 1536:2001 Centrifugally cast (spun) iron pressure pipes for water, gas and sewage (fourth revision)	Amendment No.3 July 2008	28 August 2008

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref. MTD 6/T-10]

Dr. (Mrs.) SNEH BHATLA, Scientist 'F' & Head (Met Engg.)

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का. आ. 2698.— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि अनुसूची में दिये गये मानक(कों) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :-

अनुसूची

क्रम संख्या	संशोधित भारतीय मानक (कों) की सं. वर्ष और शीर्षक	संशोधन की संख्या और वर्ष	संशोधन लागू होने की तिथि
1.	आईएस 4923:1997 खोखले हस्तात के खंड संरचनात्मक प्रयोग के लिए-विशिष्ट (दूसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 4, जुलाई, 2008	25 अगस्त, 2008

इन संशोधनों की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़ चेन्नई, मुम्बई तथा श्रृंखला कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल मुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में विक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ: एमटीडी 10/टी-30]

डा. (श्रीमति) स्नेह भाटला, वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख (एमटीडी)
New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 698.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each:

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standard(s) amendment(s)	No. & Year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
1.	IS 4923:1997 Hollow steel sections for structural use-Specification (second revision)	Amendment No.4 July, 2008	25 August 2008

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref. MTD 19/T-30]

Dr. (Mrs.) SNEH BHATLA, Scientist 'F' & Head (Met Engg.)

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2008

का. आ. 2699.— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिये गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :-

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक (कों) की सं. वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आईएस 14553:2008 स्वचल वाहन-संपीडित	14553:1998	31 जुलाई 2008

(1)	(2)	(3)	(4)
	इन्हें ई अनुसूक्त वाहनों से निष्कासित गैस की अपार्यक्त (धुआँ) के मापन का उपकरण-विशिष्ट (पहला सुधारण)		
2.	आई एस 15783:2008 सहक वाहन दो और तीन पहियों वाले मोटर वाहनों के लिए श्रेणी विवरण-विशिष्ट	10289:1982, 10841:1984 और 13493:1992	31 जुलाई 2008
3.	आई एस 15802:2008 स्वेचल वाहन एम 1 श्रेणी के वाहनों की छोड़ कर चार पहियों वाले वाहनों के लिए विशेषताएँ		31 जुलाई 2008

इस अधिनियम मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलूर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, रायपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ: टी ई डी जी-16]

राकेश कुमार, वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख (टी ई डी)

New Delhi, the 16th September, 2008

S. O. 2699.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each:

SCHEDULE

Sl. No.	No. Year & Title of the Indian Standards Established	No. & Year of Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standard	Date Established
(1)	(2)	(3)	(4)
1	IS 14553:2008 Automotive vehicles—Apparatus for the measurement of opacity (Smoke) of exhaust gas from vehicles equipped with compression ignition engines—Specification (First Revision)	14553:1998	31 July 2008

(1)	(2)	(3)	(4)
2	IS 15783:2008 Road vehicles— Brake control levers for two and three wheeled motor vehicles— Specification	10289:1982, 10841:1984 and 13493:1992	31 July 2008
3.	IS 15802:2008 Automotive vehicles— Windscreen wiping system for 4 wheelers other than M1 category of vehicles— Requirements		31 July 2008

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref. TED G-16]

RAKESH KUMAR, Scientist 'F' & Head
(Transport Engg.)

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2008

का.आ. 2700. भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिस भारतीय मानक का विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है वह स्थापित हो गया है:

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारत में मानक (कों) का ग. वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा प्रतिस्थापित भारतीय मानक अधिनियम के तहत कोई हो. की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
1.	आईएस 15788:2008 मत्स्य जाल-जाल का माइज ज्ञात करने के लिये परीक्षण पद्धति जाल का छिद्र	नहीं	जुलाई 2008

अब यह भारतीय मानक बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, के मुख्यालय मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलूर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, रायपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ: टीएसडी/जी 25]

पी. भटनगर, वैज्ञानिक 'ई' एवं प्रमुख (टीएसडी)

New Delhi, the 19th September, 2008

S.O. 2700.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each:

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Year of the Indian Standards Established	No. & Year of Indian Standard, if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Establishment
1.	IS 15788:2008 Fishing Nets- method of Test for the Determination of Mesh Size- Opening of Mesh	Nil	July 2008

Henceforth, this standard will be available for sale.

Copy of the this Standard is available for sale with H.Q. at Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and its Regional Offices at New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices at Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref. FXD/G-25]

P. BHATNAGAR, Scientist 'E' & Head (Textiles)

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2008

का.आ. 2701.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिस भारतीय मानक का विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है वह स्थापित हो गया है:-

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक की सं. वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अंशिक्रमित भारतीय मानक यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
1.	आईएस 15768:2008 बस्त्रादि-व्यवसायिक सोफासजी के लिए फर्नीचर की अग्नि अवरोधकता - विशिष्ट	नहीं	जून 2008

अब यह भारतीय मानक बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, के मुख्यालय, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयाम्बूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ: टीएक्सडी/बी-25]

पी. भटनगर, वैज्ञानिक 'ई' एवं प्रमुख (टीएक्सडी)

New Delhi, the 19th September, 2008

S.O. 2701.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed has been established on the date indicated against each:

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards Established	No. & Year of Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Establishment
1.	IS 15768:2008 Textiles—Resistance to Ignition of Upholstered Composites used For Non—Domestic Furniture—Specification	Nil	June 2008

Henceforth, this standard will be available for sale.

Copy of the this Standard is available for sale with H.Q. at Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and its Regional Offices at New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices at Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref. FXD/G-25]

P. BHATNAGAR, Scientist 'E' & Head (Textiles)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2008

का. आ. 2702.— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में वाडीनार से मध्यप्रदेश राज्य में बीना तक क्रूड आयल के परिवहन हेतु भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में, जो इससे उपबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50), की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री अरविन्द खरे, सक्षम प्राधिकारी, वाडीनार-बीना क्रूड आयल पाइपलाइन परियोजना, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, 8/5, वैशाली नानाखेडा बस स्टेण्ड के पास, उज्जैन - 456010 (मध्यप्रदेश) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील	राज्य	जिला	गुना	राज्य : मध्यप्रदेश
क्र०	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	
1	2	3	4	
1.	कजालिया	161P	0.334	
2.	नलखेडा	135	0.031	

[फा. सं. आर-31015/20/2008-ओ.आर-II]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

Ministry of Petroleum and Natural Gas

New Delhi, the 24th September, 2008

S. O. 2702.— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for transportation of Crude Oil from Vadinar in the State of Gujarat to Bina in the State of Madhya Pradesh should be laid by Bharat Oman Refineries Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri. Arvind Khare, Competent Authority, Vadinar-Bina Crude Oil Pipeline Project, Bharat Oman Refineries Limited, 8/5, "Vaishali", Near Nanakheda Bus Stand, Ujjain-456 010 (Madhya Pradesh).

SCHEDULE

TEHSIL : RAGHOGARH		DISTRICT : GUNA	STATE : MADHYA PRADESH
S.No.	NAME OF VILLAGE	SURVEY NO.	AREA IN HECTARE
1	2	3	4
1.	KAJALIYA	161 भिन	0.334
2.	NALKHEDA	135	0.031

(No. R-31015/20/2008-O.R.-II)
A. GOSWAMI, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2008

क्रा. आ. 2703.— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में वाडीनार से मध्यप्रदेश राज्य में बीना तक कूड आयल के परिवहन हेतु भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50), की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री अरविन्द खरे, सक्षम प्राधिकारी, वाडीनार-बीना कूड आयल पाइपलाइन परियोजना, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, 8/5, वैशाली नानाखेडा बस स्टेण्ड के पास, उज्जैन - 456010 (मध्यप्रदेश) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील : रातना		जिला : उज्जैन	राज्य : मध्यप्रदेश
क्र.सं.	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4
1.	लालाखेड़ी	393	0.05
2.	रुपाखेड़ी	371	0.014
3.	कुधारी	149	0.13

[फा. सं. आर-31015/22/2008-ओ.आर.-II]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

New Delhi, the 24th September, 2008

S. O. 2703.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for transportation of Crude Oil from Vadinar in the State of Gujarat to Bina in the State of Madhya Pradesh should be laid by Bharat Oman Refineries Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri. Arvind Khare, Competent Authority, Vadinar-Bina Crude Oil Pipeline Project, Bharat Oman Refineries Limited, 8/5 "Vaishali", Near Nanakheda Bus Stand, Ujjain-456 010 (Madhya Pradesh).

SCHEDULE

TEHSIL : TARANA		DISTRICT : UJJAIN	STATE : MADHYA PRADESH
S.No.	NAME OF VILLAGE	SURVEY NO.	AREA IN HECTARE
1	2	3	4
1.	LALAKHEDI	393	0.05
2.	RUPAKHEDI	371	0.014
3.	BUKHARI	149	0.13

[No. R-31015/22/2008-O.R.-II]
A. GOSWAMI, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2008

का. आ. 2704.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में वाडीनार से मध्यप्रदेश राज्य में बीना तक कूड आयल के परिवहन हेतु भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में, जो इससे उपायद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50), की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री अरविन्द खरे, सक्षम प्राधिकारी, वाडीनार-बीना कूड आयल पाइपलाइन परियोजना, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, 8/5, वैशाली नानाखेडा बस स्टैंड के पास, उज्जैन - 456010 (मध्यप्रदेश) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील : मो. बडोदिया		जिला : शाजापुर	राज्य : मध्यप्रदेश
क्र०	ग्राम का नाम	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4
1.	सागदिया	162	0.05

[फा. सं. आर-31015/23/2008-ओ.आर.-II]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

New Delhi, the 24th September, 2008

S. O. 2704.— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for transportation of Crude Oil from Vadinar in the State of Gujarat to Bina in the State of Madhya Pradesh should be laid by Bharat Oman Refineries Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri. Arvind Khare, Competent Authority, Vadinar-Bina Crude Oil Pipeline Project, Bharat Oman Refineries Limited, 8/5 "Vaishali", Near Nanakheda Bus Stand, Ujjain-456 010 (Madhya Pradesh).

SCHEDULE

TEHSIL : Mo. BADODIYA		DISTRICT : SHAJAPUR	STATE : M.P.
S.No.	NAME OF VILLAGE	SURVEY NO.	AREA IN HECTARE
1	2	3	4
1.	SAGADIYA	162	0.05

[No. R-31015/23/2008-O.R.-II]

A. GOSWAMI, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2008

का. अ. 2705.— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में वाडीनार से मध्यप्रदेश राज्य में बीना तक कूड आयल के परिवहन हेतु भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में, जो इससे उपायद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50), की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री अरविन्द खरे, सक्षम प्राधिकारी, वाडीनार-बीना कूड आयल पाइपलाइन परियोजना, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, 8/5, वैशाली नानाखेड़ा बस स्टैण्ड के पास, उज्जैन - 456010 (मध्यप्रदेश) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

सदरतील : बदनाबर		जिला : धार	राज्य : मध्यप्रदेश
क्र०	ग्राम का नाम	सर्वे नंबर	सेक्टरल हैक्टेयर में
1	2	3	4
1.	दौत्रा	670 p 829 830 1282 1319/2 1319/3	0.78 0.08 0.06 0.09 0.02 0.20
2.	बखतपुर	16 18 321	0.02 0.08 0.10
3.	टीटीकाड़ा	23	0.17
4.	शेदला	729/2	0.26
5.	तिलगारा	1193/1	0.04
6.	मुल्थान	569 910 1286 2596/2	1.85 0.23 0.34 0.21
7.	काछीबड़ोथ	573	0.03
8.	करोडा	45 56/3	0.05 0.08

New Delhi, the 24th September, 2008

S. O. 2785.— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for transportation of Crude Oil from Vadinar in the State of Gujarat to Bina in the State of Madhya Pradesh should be laid by Bharat Oman Refineries Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri. Arvind Khare, Competent Authority, Vadinar-Bina Crude Oil Pipeline Project, Bharat Oman Refineries Limited, 8/5 "Vaishali", Near Nanakheda Bus Stand, Ujjain-456 010 (Madhya Pradesh).

SCHEDULE

TEHSIL : BADNAWAR		DISTRICT : DHAR	STATE : MADHYA PRADESH
S.No.	NAME OF VILLAGE	SURVEY NO.	AREA IN HECTARE
1	2	3	4
1.	DOTRIYA	670 P	0.78
		829	0.08
		830	0.06
		1282	0.09
		1319/2	0.02
		1319/3	0.20
2.	BAKHATPURA	18	0.02
		18	0.08
		321	0.10
3.	TITIPADA	23	0.17
4.	SANDLA	729/2	0.28
5.	TILGARA	1193/1	0.04
6.	MULTHAN	569	1.85
		910	0.23
		1286	0.34
		2596/2	0.21
7.	KHACCHI BARODA	673	0.03
		678	0.20
8.	KARODA	45	0.05
		56/3	0.08

[No. R-31015/13/2004-O.R.-II]

A. GOSWAMI, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2008

क्र. आ. 2706.— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में वाडीनार से मध्यप्रदेश राज्य में बीना तक कूड आयल के परिवहन हेतु भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50), की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है:

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री अरविन्द खरे, सक्षम प्राधिकारी, वाडीनार-बीना कूड आयल पाइपलाइन परियोजना, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, 8/5, वैशाली नानाखेड़ा बस स्टैण्ड के पास, उज्जैन - 456010 (मध्यप्रदेश) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

सहस्रोल : पेटलावद		जिला : झाबुआ	राज्य : मध्यप्रदेश
क्र०	भाग का नाम	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4
1.	आबलिया	902	0.07
2.	सोपला	4	0.07
3.	आतस्याखेडी	326	0.04
		329	0.09
4.	सेधलिया	99	0.63
		107	0.14
5.	रेफरखड़ी	552	0.10
6.	हाउसपुरा	78	0.23
		285	0.15
		286	0.07

New Delhi, the 24th September, 2008

S. O. 2706- Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for transportation of Crude Oil from Vadinar in the State of Gujarat to Bina in the State of Madhya Pradesh should be laid by Bharat Oman Refineries Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri. Arvind Khare, Competent Authority, Vadinar-Bina Crude Oil Pipeline Project, Bharat Oman Refineries Limited, 8/5 "Vaishali", Near Nanakheda Bus Stand, Ujjain-456 010 (Madhya Pradesh).

SCHEDULE

TEHSIL : PETLAWAD DISTRICT : JHABUA STATE : MADHYA PRADESH			
S.No.	NAME OF VILLAGE	SURVEY NO.	AREA IN HECTARE
1	2	3	4
1.	ZHABLIYA	902	0.07
2.	SOYALA	4	0.07
3.	ALISIYA KHEDI	328	0.04
		329	0.09
4.	SEJALIYA	99	0.63
		107	0.14
5.	BEGANBARDI	552	0.1
6.	LALPURA	78	0.23
		285	0.15
		286	0.07

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2008

क्र. आ. 2707.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में वाडीनार से मध्यप्रदेश राज्य में बीना तक कूड आयल के परिवहन हेतु भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50), की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है:

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री अरविन्द खरे, सक्षम प्राधिकारी, वाडीनार-बीना कूड आयल पाइपलाइन परियोजना, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, 8/5, वैशाली नानाखेडा बस स्टैण्ड के पास, उज्जैन - 456010 (मध्यप्रदेश) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तालिका : पापडा		जिला : उज्जैन	राज्य : मध्यप्रदेश
क्र०	ग्राम का नाम	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4
1.	समाबालोदा	430	0.06
2	तुरजा खेड़ी	392	0.10
		508	0.06
		529	0.04

[प्र. सं. आर-31015/18/2008-ओ.आर.-II]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

New Delhi, the 24th September, 2008

S. O. 2707.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for transportation of Crude Oil from Vadinar in the State of Gujarat to Bina in the State of Madhya Pradesh should be laid by Bharat Oman Refineries Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri. Arvind Khare, Competent Authority, Vadinar-Bina Crude Oil Pipeline Project, Bharat Oman Refineries Limited, #/5 "Vaishali", Near Nanakheda Bus Stand, Ujjain-456 010 (Madhya Pradesh).

SCHEDULE

TEHSIL : NAGDA		DISTRICT : UJJAIN		STATE : MADHYA PRADESH	
S.No.	NAME OF VILLAGE	SURVEY NO.		AREA IN HECTARE	
1	2	3		4	
1.	RAMABALODA	430		0.06	
2	SURJAKHEDI	392		0.10	
		506		0.06	
		529		0.04	

[No. R-31015/18/2008-O.R.-II]
A. GOSWAMI, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2008

का. आ. 2708.— जबकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में भारत सरकार की निम्नलिखित अनुसूची में, दि. 9.11.99 की 3280, दि. 24.12.99 की 3673, दि. 30.03.2000 की 791 और दि. 10.07.2001 की 1624 अधिसूचनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार निदेशित करता है कि सभी प्रकार के भार से मुक्त होकर मोटर स्प्रिट, सुपीरियर किरासिन और हाई स्पीड डीजल के परिवहन हेतु पाइपलाइन बिछाने के लिए केरल राज्य के इरिम्पनम, कोच्चि में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इरिम्पनम संस्थापना से तमिलनाडु राज्य के करूर तक उक्त भूमि के उपयोग का अधिकार पेट्रोनेट सीसीके लिमिटेड में निहित है और मेसर्स पेट्रोनेट सीसीके लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाया जाना चाहिए ;

और जबकि पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन) नियम, 1963 के स्पष्टीकरण 1 के अधीन अपेक्षित जैसे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना, दिनांक 11.06.2004 का एस.ओ. 1427 द्वारा केंद्र सरकार, दिनांक 15.12.2002 को केरल राज्य में पाइपलाइन बिछाए जाने के बाद प्रचालन की समापन तिथि घोषित की है ;

अब, मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को उक्त भूमि से उपयोग के अधिकार से बीपीसीएल कोच्चि रिफ़ाइनरी से नेडुम्बाशोरी स्थित कोचिन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन तक एटीएफ उत्पाद के परिवहन के लिए एटीएफ पाइपलाइन बिछाने का इरादा है ;

और जबकि कोचिन-कोयम्बतूर-करूर पाइपलाइन बिछाने के लिए काम में लाए उपयोग के अधिकार में ही एटीएफ पाइपलाइन बिछाने को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अनुमति देने में पेट्रोनेट सीसीके लिमिटेड को कोई आपत्ति नहीं है ;

और जबकि केंद्र सरकार को अनुरोध पर विचार किए जाने पर इस पर विश्वास है कि कोच्चि रिफ़ाइनरी से कोचिन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन तक एटीएफ उत्पाद के परिवहन के लिए एटीएफ पाइपलाइन बिछाने के लिए उक्त भूमि अपेक्षित है ;

और आगे, उक्त अधिनियम की धारा 6 की धारा (4) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा निदेश देता है कि कोच्चि रिफ़ाइनरी से कोचिन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन तक एटीएफ उत्पाद के परिवहन के लिए एटीएफ पाइपलाइन बिछाने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार को काम में ला सकता है और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाए जाएंगे ;

अनुसूची

क्रम सं.	एस ओ नं एवं तिथि	गाँव का नाम	ताल्लुक	ज़िला	राज्य
1	2	3	4	5	6
1	दि. 9.11.99 का 3280	पारक्कडवु (ब्लॉक नं.5)	आलुवा	एरणाकुलम	केरल
		पारक्कडवु (ब्लॉक नं.6)	आलुवा	एरणाकुलम	केरल
		कुन्नुकरा	परथूर	एरणाकुलम	केरल
2	दि. 24.12.99 का 3673	तुक्काक्करा (उ) (ब्लॉक नं.6)	कणयन्नूर	एरणाकुलम	केरल
		काक्कनाड (ब्लॉक नं.9)	कणयन्नूर	एरणाकुलम	केरल
		आलुवा पश्चिम (ब्लॉक नं.37)	आलुवा	एरणाकुलम	केरल
		आलुवा पश्चिम (ब्लॉक नं.34)	आलुवा	एरणाकुलम	केरल
		पारक्कडवु (ब्लॉक नं.5)	आलुवा	एरणाकुलम	केरल
		पारक्कडवु (ब्लॉक नं.6)	आलुवा	एरणाकुलम	केरल
		कडुडल्लूर	परथूर	एरणाकुलम	केरल
		करुमल्लूर	परथूर	एरणाकुलम	केरल
3	दि. 30.3.2000 का 791	तुक्काक्करा (उ) (ब्लॉक नं.6)	कणयन्नूर	एरणाकुलम	केरल
		आलुवा पश्चिम (ब्लॉक नं.37)	आलुवा	एरणाकुलम	केरल
		आलुवा पश्चिम (ब्लॉक नं.34)	आलुवा	एरणाकुलम	केरल
		पारक्कडवु (ब्लॉक नं.5)	आलुवा	एरणाकुलम	केरल
		पारक्कडवु (ब्लॉक नं.6)	आलुवा	एरणाकुलम	केरल
		कुन्नुकरा	परथूर	एरणाकुलम	केरल
		करुमल्लूर	परथूर	एरणाकुलम	केरल
		कडुडल्लूर	परथूर	एरणाकुलम	केरल
4	दि. 10.7.2001 का 1624	तिरुवानकुलम (ब्लॉक नं.10)	कणयन्नूर	एरणाकुलम	केरल
		कडुडल्लूर	परथूर	एरणाकुलम	केरल

[अ. सं. आर-31015/27/2008-ओ.आर-II]

ए. गोस्वामी, अपर सचिव

New Delhi, the 24th September, 2008

S. O. 2708.—Whereas by the notifications of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number 3280 dated 9.11.99, 3673 dated 24.12.99, 791 dated 30.3.2000 and 1624 dated 10.7.2001 in the following schedule, the Central Government directed that Right Of User in said land vest in the Petronet CCK Limited free from all encumbrances for the purpose of laying pipeline for the transportation of motor spirit, superior kerosene and high speed diesel from the Irimpanam installation of Bharat Petroleum Corporation Limited, Irimpanam, Kochi in the State of Kerala to Karur in the State of Tamil Nadu and pipelines should be laid by M/s.Petronet CCK Limited;

And whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O . 1427 dated 11.06.2004, as required under explanation-1 of the rule of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules 1963, the central government declared the date 15.12.2002 as date of termination of operation in the State of Kerala after the pipeline has been laid:

Now, M/s.Bharat Petroleum Corporation Limited intends to lay ATF pipeline for the purpose of transportation of ATF product from BPCL's Kochi Refinery to Cochin International Airport at Nedumbassery through the ROU in the said land;

And whereas Petronet CCK Limited has no objection in permitting Bharat Petroleum Corporation Limited for laying ATF pipeline in the same ROU used for laying Cochin-Coimbatore-Karur pipeline:

And whereas Central Government after considering the request, satisfied that the said land are required for laying of ATF pipeline for transportation of ATF product from Kochi Refinery to Cochin International Airport;

And further, in exercise of the powers conferred by section (4) of section 6 of the said act, the Central Government hereby directs that right of user in the said land shall be used by Bharat Petroleum Corporation Limited for laying ATF pipeline from Kochi Refinery to Cochin International Airport and pipelines should be laid by M/s.Bharat Petroleum Corporation Limited;

SCHEDULE

Sl. No.	S.O.No. and Date	Name of Village	Taluk	District	State
1	2	3	4	5	6
1	3280 dated 9.11.99	Parakkadavu (Block No.5) Parakkadavu (Block No.6) Kunnukara	Aluva Aluva Paravur	Ernakulam Ernakulam Ernakulam	Kerala Kerala Kerala
2	3673 dated 24.12.99	Thrikkakara(N)(Block No.6) Kakkanad (Block No.9) Aluva West (Block No.37) Aluva West (Block No.34) Parakkadavu (Block No.5) Parakkadavu (Block No.6) Kadungallur Karumallur	Kanayannur Kanayannur Aluva Aluva Aluva Aluva Paravur Paravur	Ernakulam Ernakulam Ernakulam Ernakulam Ernakulam Ernakulam Ernakulam Ernakulam	Kerala Kerala Kerala Kerala Kerala Kerala Kerala Kerala
3	791 dated 30.3.2000	Thrikkakara North (Block No.6) Aluva West (Block No.37) Aluva West (Block No.34) Parakkadavu (Block No.5) Parakkadavu (Block No.6) Kunnukara Karumallur Kadungallur	Kanayannur Aluva Aluva Aluva Aluva Paravur Paravur Paravur	Ernakulam Ernakulam Ernakulam Ernakulam Ernakulam Ernakulam Ernakulam Ernakulam	Kerala Kerala Kerala Kerala Kerala Kerala Kerala Kerala
4	1624 dated 10.7.2001	Thiruvankulam (Block No.10) Kadungallur	Kanayannur Paravur	Ernakulam Ernakulam	Kerala Kerala

[No. R-31015/27/2008-O.R.-II]
A. GOSWAMI, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2008

का. आ. 2709.— केंद्रीय सरकार, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना, दिनांक 1 जून, 2005 का एस.ओ. 1998 के आशोधन में और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसार, केंद्र सरकार एतद्द्वारा श्री पी एन मोहनचंद्रन, प्रबंधक (विधि प्रशासन), पेट्रोनेट सीसीके लिमिटेड को कोचिन-कोयम्बतूर-करूर पाइपलाइन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में उनके कार्य के अतिरिक्त, उपर्युक्त अधिनियम के अधीन केरल राज्य के अंतर्गत, कोच्चि रिफ़ाइनरी से लेकर कोचिन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन तक कोचिन-कोयम्बतूर-करूर पाइपलाइन के लिए पेट्रोनेट सीसीके लिमिटेड द्वारा अर्जित आरओयू में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एटीएफ पाइपलाइन बिछाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के कार्य करने को प्राधिकृत करता है।

[फ़. सं. आर-31015/27/2008-ओ.आर.-II]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

New Delhi, the 24th September, 2008

S. O. 2709.— In modification of notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.1996 dated 1st June, 2005 and in pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisitions of Right of User in Land) Act, 1962, the Central Government hereby authorizes Shri.P.N.Mohanachandran, Manager (Legal Administration), Petronet CCK Limited, to perform the functions of the competent authority for laying an ATF pipeline by Bharat Petroleum Corporation Limited from Kochi Refinery to Cochin International Airport, in the ROU acquired by Petronet CCK Limited for Cochin-Coimbatore-Karur pipeline, in addition to his function of the competent authority for Cochin-Coimbatore-Karur pipeline, under the said Act within territory of Kerala.

[No. R-31015/27/2008-O.R.-II]

A. GOSWAMI, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2008

का.आ. 2710.— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि कर्नाटक राज्य में देवनगोंदी से नया बेंगलोर अन्तर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट, देवनहल्ली, तक पेट्रोलियम उत्पादन के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करना आवश्यक है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त अनुसूची में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिनों के भीतर, भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन या भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के संबंध में लिखित रूप में आक्षेप श्री आर. आर. जन्तू, सक्षम प्राधिकारी (कर्नाटक), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एटीएफ पाइपलाइन परियोजना, नं 719, 4 वास, 7 मैन कल्याण नगर, 1 ब्लॉक बेंगलोर-560043, कर्नाटक को भेज सकेगा।

अनुसूची

तालूका : यलहंका		जिला : बेंगलोर अर्बन		राज्य : कर्नाटक	
गाँव का नाम	सर्वे नंबर	हिस्सा नंबर	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6

होब्ली : जाला

दुम्पनहल्ली

41

-

0

36

31

New Delhi, the 26th September, 2008

S. O. 2710.— Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Devanagondhi to New Bangalore International Airport Devanahalli in the State of Karnataka, a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land, to Shri.R.R.Jannu, Competent Authority (Karnataka), Indian Oil Corporation Limited, ATF Pipeline Project , No.719, Ground Floor, 4th Cross, 7th Main, Kalyna Nagar, 1st Block Bangalore-560043 (Karnataka).

SCHEDULE**Taluk : Yalahanka****District : Bangalore Urban****State : Karnataka**

Name of the Village	Survey no.	Sub-Division no.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6

Hobli : Jala**DHUMMANAHALLI**

41

-

0

36

31

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2008

का.आ. 2711.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इलाहाबाद बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 1221/08) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 28-8-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/41/2004-आई. आर. (वी. II)]

राजिन्द्र कुमार, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 29th August, 2008

S.O. 2711.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 1221-08) of the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of Allahabad Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 28-08-2008.

[No. L-12012/41/2004-IR(B-II)]

RAJINDER KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE**BEFORE SHRI P. R. DAVE, PRESIDING OFFICER
INDUSTRIAL TRIBUNAL, AHMEDABAD**

Reference (ITC) No. 1221/08

(Old) Reference (C.G.I.T.A) No. 1456/04

ADJUDICATION**BETWEEN**

The Assistant General Manager,
Allahabad Bank,
Regional Office,
2nd Floor, Navin House,
Opp. Sardar Patel Sewa Samaj Bhavan,
C.G. Road, Navrangpura,
Ahmedabad-380006 (Gujarat)

... First Party

AND

Shri Sunil K. Patel,
Flat No. A 208
Shrinath Complex,
Swastik Park Society,
Near Shrinath Marble,
Alham Road, Bhatar,
Surat-395017 (Gujarat)

... Second Party

Dispute pertaining to
termination of the
services of the
workman, Shri Sunil K.
Patel

APPEARANCES

Advocate, Ms. S. N. Bhavsar for the first party.

Advocate, Shri Hitesh D. Katharotiya for the Second party.

AWARD

1. The Under Secretary, Ministry of Labour, Government of India, New Delhi has referred to this Tribunal, the dispute between above parties, for adjudication, vide its letter dated 27-06-2004. The dispute is shown in the Schedule as under :—

SCHEDULE

“Whether the action of the management of Allahabad Bank through the Assistant General Manager in terminating the services of Shri Sunil K. Patel by way of ‘dismissal without notice’ w.e.f. 3-3-2003 is legal, proper and justified? If not, what relief the concerned workman, Shri Sunil K. Patel is entitled to and from which date and what other directions are necessary in the matter?”

2. Both the parties are served with notice and parties appeared before the Tribunal through their Advocates.

3. In the course of hearing the matter, the second party has filed withdrawal purshis Ex. 11 and submitted before this Tribunal that as the second party and the first party Bank has settled the matter, the second party wanted to withdraw this matter and sought for permission to withdraw the Reference.

4. In view of these submissions, this Tribunal recorded the withdrawal purshis granting the permission to withdraw the Reference as prayed for. Therefore, I pass the following order in this Reference.

ORDER

The withdrawal purshis Ex. 11 is allowed and permission is granted to withdraw this Reference as prayed for. No order as to the costs.

Date : 31-7-2008

P. R. DAVE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 जुलै, 2008

का.आ. 2712.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, सो. पी. डब्ल्यू. डी. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 1554/2008) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल 42012/481/2005 आई. आर. (सी.एल-10)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st September, 2008

S.O. 2712.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. 1534/2008) of the Industrial Tribunal, Ahmedabad (Gujarat) as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of Gandhinagar Electrical Division, Central Public Works Department, 2/44-A/14, Kalu Sarai, and their workmen, which was received by the Central Government on 1-9-2008.

[No. L-42012/181/2005-IR (CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT

AHMEDABAD

BEFORE SHRI Y. P. BHATT

Reference (ITC) 1534/08/

Old No. Reference (C.G.I.T.A.) No. 175/60

ADJUDICATION

BETWEEN

1. The Executive Engineer (Electrical),
Gandhinagar Electrical Division, CPWD,
Second Floor, Nirman Sadan,
Sector-10/A, CHH-3,
Gandhinagar.

2. The Assistant Engineer (Electrical),
Central Public Works Department,
Baroda Central Electrical Sub Station,
Dak Bungalow, Fatehgunj Circle,
Vadodara (Gujarat) - 390 002.

3. The Superintending Engineer (Electrical),
Central Public Works Department,
Mumbai Central Electrical Circle,
Second Floor, New C.G.O. Building
New Marine Lines,
Mumbai-400 020.

4. M/s. Swastik Enterprises,
2/44-A/14, Kalu Sarai,
Behind Hauz Khaz Terminal,
Hauz Khas, New Delhi-110 016.

...First Party

AND

Shri Vijay Haribhai Parmar & 5 Others,
10/1701, Sanskar Nagar Apartment,
Near Gayatri Nagar,
Gotri, Vadodara (Gujarat) - 390 021.

...Second party

APPEARANCES

Shri R. S. Munshi for the first party.

No one appeared for the second party.

AWARD

This Industrial Dispute between the above said parties was referred by the Desk Officer, Government of India, Ministry of Labour, New Delhi vide order No. L-42012/181/2005-IR (CM-II) dated 14-09-2006 to the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ahmedabad for adjudication under Section 10 (1) of the Industrial Disputes Act, 1947. The said dispute was

subsequently transferred to this Tribunal by order of the competent authority. The dispute between the parties relates to the following demands of the workmen concerned.

“Whether the action of the management of Central Public Works Department, Gandhinagar in terminating the services of Sh. Vijay Haribhai Parmar and 5 others from the date of their respective termination as per list enclosed, is legal and justified? If not, to what relief the concerned workmen are entitled?”

After the case was transferred to this Tribunal, the notices were sent to the parties. It appears that there are in all six workmen concerned in this case. The main workman is Vijay Haribhai Parmar of whose address is given in the order of Reference. Said Vijay Haribhai Parmar was served as per Ex. 5, however, neither he nor his fellow workmen are attending this Tribunal. It therefore appears that none of the workmen have any interest in this case. This Reference case is, therefore, dismissed for want of prosecution. Order accordingly with no order as to costs.

Ahmedabad

Dated : 8-8-2008

Y. P. BHATT, Industrial Tribunal (Central)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2008

का.आ. 2713.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डाक विभाग के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या ---) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40011/26/95-आई आर (डी.यू.)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st September, 2008

S.O. 2713.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. ---) of the Industrial Tribunal/Labour Court, Ahmedabad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Department of Posts and their workman, which was received by the Central Government on 1-9-2008.

[No. L-40011/26/95-IR (DU)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI Y. P. BHATT, INDUSTRIAL TRIBUNAL,
AHMEDABAD, GUJARAT

Vadodara No. Ref. (ITC) No. 4 of 1996
CGIT, A'bad No. Ref. CGITA No. 34 of 2007
(State Ind. Tribunal, A'bad No.
Reference (IT-C) No. 1585 of 2008

ADJUDICATION BETWEEN**Management of Post: Through**

1. The Chief Post Master General, Ahmedabad.

2. The Sr. Post Master, Raopura, Vadodara.

3. The SSP Vadodara. ... First party

AND

The workmen ... Second party,

In the matter of termination of service of Shri G. S. Dudhwala.

APPEARANCE

Shri PM Rami, the learned Assistant Govt. Pleader for the first party.

Shri Bharat T. Majmudar, the learned Advocate for the second party.

AWARD

The Ministry of Labour in Government of India referred this industrial dispute between the aforesaid parties vide its order No. L-40011/26/95-IR(DU) dated 27-06-1996 firstly to the Industrial Tribunal, Vadodara. Subsequently on establishment of CGIT-cum-Labour Court here at Ahmedabad, this dispute was transferred to the said CGIT vide orders of the competent authorities. Thereafter, by an order of Hon. High Court of Gujarat, this dispute along with the other disputes pending with the CGIT were transferred to the State Industrial Tribunal at Ahmedabad. The registration number of this dispute is, therefore, recorded for all the three Tribunals. The dispute relates to the following demand of the workmen as stated in the schedule to the order of Reference:

"Whether the action of management of Chief Post Master General, Vadodara Region Ahmedabad Post Master, Raopura Branch, Vadodara and SSP Vadodara, East Division, Vadodara in terminating the services of Shri G. S. Dudhwala is justified? If not to what relief the workman is entitled to?"

2. Shri G. S. Dudhwala, hereinafter referred to as "The workman" filed statement of claim at Ex. 7 and stated therein that he was working under the first party, hereinafter referred to as "The employer" on the vacant post of packer from 13-08-1986 and his services were terminated by an oral order dated 31-08-1988. It is stated by the workman that he was not issued any charge sheet, memo etc. and that his services were satisfactory; that before terminating his services, no due procedure was followed nor any opportunity of hearing was given and therefore, his termination amounts to illegal retrenchment. The workman has also stated the numbers of days he worked in a tabular form and submitted that he had completed 240 days services continuously and the termination of his service by an oral order being illegal, he is entitled to be reinstated in service with full wages. It is alleged that the employer has adopted tactics of perpetual ad-hocism; that junior persons are

retained; that during the conciliation proceeding the management had stated that it is because of the desire of the authorities that the workman is not being reinstated. The authorities remained present during the conciliation but did not concede to his claim and hence the conciliation officer had to make a failure report. The workman also stated that he is out of job since his termination and accordingly it is prayed that he may be reinstated with full back wages and continuity of service etc.

3. The employer filed defence statement at Ex. 13 and denied various contentions raised by the workman in the statement of claim. It is submitted by the employer that the workman was engaged in leave period of various permanent Group - D officials by the Sr. Post Master, Vadodara Head Office. It is denied that the workman was appointed on clear vacant post. It is again stated that he was engaged on short term periods of leave of permanent Group - D officials and when their leave was over, such staff joined their duties and hence the workman cannot be continued against the same post; that it was a contract of specific short term leave period of permanent staff. It is also submitted by the employer that the workman was not recruited through the departmental due procedure and he was not regularly appointed and therefore, there is no provision to issue chargesheets etc.; that in fact when the permanent group - D staff joins his duty, the workman has to go home; that the behaviour, attitude of the workman etc. has no relevance; that the workman cannot in any circumstances can possess the status of the regular employee of the department and therefore, there is no question of his reinstatement; that no juniors were retained or absorbed as alleged by the workman. It is submitted by the employer that lastly the workman was engaged for two days i.e. For 01-09-88 and 02-09-88 and the conciliation proceedings were held; on 25-12-1994. Thus, there was abnormal delay on the part of the workman; that since the workman had not fulfilled the conditions for recruitment i.e. nomination through the Employment Exchange, examination, selection etc. he had no locus standi for being absorbed in the department of the employer. It is also contended by the employer that the department is not an industry within the Industrial Disputes Act. After certain repetition, the employer requested to dismiss this Reference case.

4. The workman deposed at Ex. 19 wherein he stated that he was appointed by Senior Post Master and was working in Raopura Post Office, that he was appointed in clear vacancy of Group 'D' staff and worked as such from 13-08-86 to 31-08-88. He was orally discharged; no compensation was paid; that he filled up bond of Rs. 1000 that he had worked for 582 days; that KM Saiyad and KG Adhyaru have been appointed after him and are still working. In the cross examination, the workman stated that he was failed in SSC and that his interview was not held and was directly taken. He denied that he was taken on work in place of permanent employee when they proceeded

on leave. He was not given identity card nor he was given other facility; that he was given salary after obtaining signature in the pay roll. He denied that he cannot read and write in English. He admits that he was not given order in writing by the employer. He finally admits that he was given work when the permanent employee of the department proceeds on leave.

5. Considering the deposition of the workman, the days of his service does not seem to be challenged by the employer in the cross examination. Similarly, his allegation that KM Saiyad and KG Adhyaru who were taken after him were continued in the service is also not challenged in the cross examination. The only material admission that was obtained in the cross examination was that he was given work when the permanent 'D' staff proceeds on leave. He has denied that he had not worked continuously.

6. The employer examined Shri Panabhai Chhaganbhai Garnit as its witness at Ex. 37 who is Deputy Post Master at Vadodara. He admits that the workman was working on daily wages basis and was given work when permanent employee proceeds on leave; that he was paid wages for the days he had worked; that he was given work with a view that the work of postal department may not be stopped in the absence of the permanent employee. It is stated by the witness that he was not appointed as per rules of the Government. In the cross examination, the witness was shown Ex. 20 which is the details of presence of the workman produced by the employer vide list Ex. 14. The witness states that the muster roll and pay roll of the workman are in the custody of the accounts office. He states that the Post Master can retain outsider on work; that in 1986 the qualification for Group 'D' was seventh standard pass. The witness admits that the work which was taken from the workman was that of a permanent employee in the later's absence. Rest of the cross examination does not seem to be material for the purpose of this case.

7. If we consider the deposition of the witness of the employer, only one fact is coming out and that is - the workman was given work when the permanent employee proceeds on leave. It appears that at the relevant time the workman being SSC failed, was having qualification for being appointed as Group 'D' staff.

8. The first closing pursish of workman is at Ex. 28 and second is at Ex. 60. Similarly, the employer has also given two closing pursish vide Ex. 38 and 65. The written arguments of the workman is at Ex. 66 and that of the employer is at Ex. 76. I have considered the rival contentions of the parties in the written arguments together with the evidence on record.

9. The undisputed fact is that the workman had entered the service of the employer on 13-08-1986 and had worked up to 02-09-1988. Barring August and September, 1986, and the last month September, 1988, the workman

had put in 23 to 30 days work in each month. Indisputably, the workman had put in more than 294 days of service within twelve months prior to his termination. Admittedly, he was not given notice of retrenchment, nor retrenchment compensation was offered or given to him. The only defence of the employer as is appear from the record is that the workman was given work because the permanent Group 'D' employee had proceeded on leave and also with a view to see that the work of the post office should not be stopped. If we go through Sec. 25F of the Industrial Disputes Act, wherein conditions precedent to retrenchment of workmen is stated, we do not find a provision that if a workman is retained to do work of a permanent employee continuously for more than two years, he can be discharged without payment of retrenchment of compensation etc. Therefore, in the humble opinion of this Tribunal, the so called termination of the workman on 02-09-1988 was retrenchment of the workman and since the conditions precedent were not followed by the employer, the said retrenchment was in violation of the provisions of the Industrial Disputes Act. In the written arguments of the employer it is contended that the workman cannot be considered to be permanent because his appointment was not done after written test, oral interview etc. Sec. 25F of the Industrial Disputes Act also does put a condition that the workman concerned should be a permanent workman and should have been appointed after written test, oral interview etc. The contention in the written arguments of the employer that the workman had not completed 240 days in any of the year is devoid of any merits because it is against the record produced in this case.

10. From Ex. 20 it also does not appear that the workman was given work only when the permanent employee proceeds on leave. On several occasions the workman was given work on vacant post which fell vacant on account of retirement of concerned employee. On several occasion the workman was given work because the holder of the said post was sent on deputation to somewhere else. Thus, the workman had rightly contended in the statement of claim as also in his deposition that he was given work on vacant post.

11. The learned Assistant Government Pleader drew my attention to the written arguments of the employer and submitted that postal department is not an industry within the definition of the "industry" given in the Industrial Disputes Act, 1947. He also cited decision of Hon. Supreme Court in Sub-Divisional Inspector of Post, Vaikam and Others Versus Theyyam Joseph etc. which was published in 1996 II LLJ 230. I have gone through the said decision. It was held by Hon. Supreme Court that to provide telecommunication service to the general public and amenity, was essential part of the sovereign function of the welfare state and hence the postal department was not an industry as defined in the Industrial Disputes Act. The learned AGP has also produced Swamy's Service Rules for

the ED Staff which were discussed in the said decision of Hon. Supreme Court. The present workman was not from ED staff. It was not the case of any of the parties that the workman was covered by the ED staff. If that be so, he ought to have been selected by a due process governed by said Swamy's service rules for ED staff. If that be so, he could not have been discharged without following those rules. The fact is, the present workman was not covered by those rules and hence those rules have no application to present case.

12. The decision of Hon. Apex Court in Sub-Divisional Inspector of Post, Vaikam Vis. Theyyam Joseph etc. 1996 II L.J. 230 was rendered by a Two Judge Bench and the same was subsequently held by a Three Judge Bench of Hon. Apex Court as not laying down the correct law. The later decision came to be published in 1998 I LLJ 255 in General Manager, TELECOM and Srinivasa Rao S. and Others. At para 5 of the decision the Hon. Supreme Court stated : --

5. A two judge Bench of this Court in Theyyam Joseph's case (supra) held that the function of the Postal Department are part of the sovereign functions of the State and it is, therefore, not an 'industry' within the definition of Section 2(j) of the Industrial Disputes Act, 1947. Incidentally, this decision was rendered without any reference to the seven Judge Bench decision in Bangalore Water Supply (supra). In a later two Judge Bench decision in Bombay Telephone Canteen Employees' Association case (supra), this decision was followed for taking the view that the Telephone Nigam is not an 'industry'. Reliance was placed in Theyyam Joseph's case (supra) for that view. However, in Bombay Telephone Canteen Employees' Association case (i.e. The later decision), we find a reference to the Bangalore Water Supply case. After referring to the decision in Bangalore Water Supply case (supra) it was observed that if the doctrine enunciated in Bangalore Water Supply case is strictly applied, the consequence is 'catastrophic'. With respect, we are unable to subscribe to this view for the obvious reason that it is in direct conflict with the seven Judge Bench decision in Bangalore Water Supply case (supra) by which we are bound. It is needless to add that it is not permissible for us, or for that matter any Bench of lesser strength, to take a view contrary to that in Bangalore Water Supply case (supra) or to bypass that decision so long as it holds the field. Moreover, that decision was rendered long back nearly two decades earlier and we find no reason to think otherwise. Judicial discipline requires us to follow the decision in Bangalore Water Supply case (supra). We

must, therefore, add that the decision in Theyyam Joseph case (supra) and Bombay Telephone Canteen Employees' Association case (supra) cannot be treated as laying down the correct law. This being the only point for decision in this appeal, it must fail.

I am of the view that in view of the aforesaid later decision, the decision cited by learned AGP in Theyyam Joseph's case will not be applicable to present case. The postal department is an 'industry' and the present workman was 'workman' within the meaning of the Industrial Disputes Act.

13. Even otherwise also, in Sec. 2 which defines various clauses of the Industrial Disputes Act, there is definition of 'public utility service' under Sec. 2(n)(iii) and postal, telegraph or telephone services are held to be public utility service. The first Schedule to the said Act enumerates various industries which may be declared as public utility services by the appropriate Government. Sec. 22 imposes a ban on STRIKE in the public utility service without certain formalities otherwise strike could be held to be illegal. Presently, even the telephone services, cellular phone services and courier services are being entrusted to the private parties with certain regulatory restrictions and therefore, perhaps such industry may not be called part of sovereign function of the State.

14. The retrenchment of the workman was, therefore, illegal. The question is, should he be reinstated? Ordinarily, when retrenchment is held to be illegal, the workman concerned has to be reinstated. There are decisions that it is not necessary to award reinstatement in every case where the retrenchment is held to be illegal. In the view of this Tribunal, each case must be examined on its own merits. There is no dispute that the workman had continuously worked for more than two years. The employer has also not refuted the contention of the workman that his Juniors have been continued. The workman had also given names of his junior workers. The witness of the employer has also admitted that presently there are 37 posts of Group 'D'. The circumstances that the workman had even worked on vacant post when the regular employees were sent on deputation, All these facts shows that workman should be ordered to be reinstated with continuity of service.

15. So far as the back wages are concerned, the same cannot be awarded to the workman. The reason being that the workman was retrenched on 02-09-1988. We do not know when he started the proceeding before conciliation officer but there is one contention of the workman in the statement of claim at paragraph 8 and that is admitted by the employer in the defence statement at paragraph 11 that the conciliation proceedings were held on 25-12-1994. We do not know that it was the only date and on no other dates the conciliation proceedings were held. It may be presumed from the aforesaid facts that there was some delay on the part of the workman, but in the absence of the statutory limitation such delay may not disentitle the

workman from claiming the relief of reinstatement so far as present case is concerned, but he can certainly be denied the monetary benefit in the nature of back wages. Another aspect of the matter is that though the oral evidence of the employer was over on 07-01-2003, neither the workman nor his representative argued their case before the Industrial Tribunal, Vadodra where the case was being conducted initially. The workman must also have earned some thing during the period of his unemployment. This Tribunal, therefore, is not inclined to grant any back wages to the workman. In the result, I pass the following order :—

ORDER

This Reference case is allowed. The action of the concerned Postal Authorities as stated in the schedule to the order of Reference in terminating the services of Shri G.S. Dudhwala is held to be unjustified. The workman is held entitled to reinstatement with continuity of service but without back wages. The said Postal Authorities shall reinstate the said workman within one month from the date of publication of this award.

There is no order as to costs.

Date : 13th August, 2008

Y. P. BHATT, Industrial Tribunal

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2008

का.आ. 2714.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकांश नं. 1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 179/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/54/2001-आई. आर. (सी.एम.-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd September, 2008

S.O. 2714.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.179/2002) of the Central Govt. Industrial-Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, which was received by the Central Government on 2-9-2008.

[No. L-22012/54/2001-IR (CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORESHRIGYANENDRAKUMARSHARMA,
PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVT.
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1,
CHANDIGARH

Case No. I.D 179/2002

Sh Darshan Dyal,
C/o General Secretary,
Trade Union Council,
Patiala.

.....Applicant

Versus

- (1) The Asstt. Manager (D), Food Corporation of India,
Dharamkot
(2) Sr. Regional Manager, FCI, Punjab Region, Sec. 34-A,
ChandigarhRespondent

APPEARANCES

For the Workman : None
For the Management : Sh. N. K. Zakhmi

AWARD

Passed on-13-8-2008

Central Govt. vide notification No. L-22012/54/2001-IR (CM-II), dated 29-8-2002 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication.

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in terminating the services of Sh. Darshan Dyal S/o Sh. Ral Lal is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to and from which date?"

2. No one is present on behalf of workman. Learned representative of the management Shri N. K. Zakhmi is present. Since morning this reference has been called number of times. At 10.45 a.m. it was ordered to be placed before this Tribunal once again at 2 p.m. It is 2.30 now and on repeated calls no one is present, in spite of having of full knowledge of the proceedings of this reference. The reference is as old as referred to this Tribunal in the year 2002. On repeated calls since morning no one is present. Accordingly, the reference is dismissed in default for non-prosecution. Central Government be informed accordingly. File to be consigned.

Chandigarh

Dated: 13-8-2008

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2008

का.आ. 2715.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकांश नं. 1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 141/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/80/2001-आई. आर. (सी.एम.-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd September, 2008

S.O. 2715.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.141/2002) of the Central Govt. Industrial-Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, which was received by the Central Government on 2-9-2008.

[No. L-22012/80/2001-IR (CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVT.
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH****Case No. I.D 141/2002**

Sh. Jarnail Singh,
C/o General Secretary,
Trade Union Council,
Patiala.

... Applicant

Versus

(1) The Asstt. Manager (D), Food Corporation of India,
Dharamkot.

(2) Sr. Regional Manager, FCI, Punjab Region, Sec. 34-A,
Chandigarh

... Respondent

APPEARANCES

For the Workman : None
For the Management : Sh. N. K. Zakhmi

AWARD

Passed on-13-8-2008

Central Govt. vide Notification No. L-22012/80/2001-IR (CM-II), dated 24-7-2002 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication.

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in terminating the services of Sh. Jarnail Singh S/o Sh. Bachan Singh is legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled to ?"

2. No one is present on behalf of workman. Learned representative of the management Shri N. K. Zakhmi is present. Since morning this reference has been called number of times. At 10.45 a.m. it was ordered to be placed before this Tribunal once again at 2 p.m. It is 2.30 now and on repeated calls no one is present, in spite of having of full knowledge of the proceedings of this reference. The reference is as old as referred to this Tribunal in the year 2002. On repeated calls since morning no one is present. Accordingly, the reference is dismissed in default for non-prosecution. Central Government be informed accordingly. File to be consigned.

Chandigarh

Dated: 13-8-2008

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2008

का.आ. 2716.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूचना में, केंद्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधन के संघर्ष, नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 87/2001) को प्रकटित करती है, जो केंद्रीय सरकार को 3-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एन-40012/524/2000 आई आर (डीयू)]

अजय कुमार गौर, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 3rd September, 2008

S.O. 2716.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 87/2001) of the Central Govt. Industrial-Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh now as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom, and their workman, which was received by the Central Government on 3-9-2008.

[No. L-40012/524/2000-IR (DU)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVT.
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH****Case No. I.D 87/2001**

Sh. Jaswant Singh,
S/o Sh. Nathu Singh,
C/o N. K. Jeet, 27349,
Lal Singh Basti Road, Bhatinda
(Punjab) 151001

... Applicant

Versus

(1) The Divisional Engineer, Telegraph, Microwave
Maintenance, Bhatinda (Punjab) 151001

... Respondent

APPEARANCES

For the Workman : None
For the Management : Sh. Anish Babbar

AWARD

Passed on-12-8-2008

Central Govt. vide Notification No. L-40012/524/2000-IR (DU), dated 31-1-2001 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication.

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in terminating the services of Sh. Jaswant Singh S/o Sh. Nathu Singh is just and legal ? If not, to what relief the workman is entitled and from which date?"

2. No one is present on behalf of workman. Learned representative of the management Shri Anish Babbar is present. Since morning this reference has been called number of times. At 10.45 a.m. it was ordered to be placed before this Tribunal once again at 2 p.m. It is 2.30 now and on repeated calls no one is present, in spite of having of full knowledge of the proceedings of this reference. The reference is as old as referred to this Tribunal in the year 2001. On repeated calls since morning no one is present. Accordingly, the reference is dismissed in default for non-prosecution. Central Government be informed accordingly. File to be consigned.

Chandigarh

Dated: 12-8-2008

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2008

क्र. उ. 2717.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसार में केन्द्रीय सरकार मै. बी.बी.एम.बी. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 117/93) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/80/92-आई आर(डीयु)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 3rd September, 2008

S.O. 2717.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 117/93) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh, now as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. BBMB, and their workman, which was received by the Central Government on 3-9-2008.

[No. L-42012/80/92-IR(DU)]
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM-LABOUR COURT-1,
CHANDIGARH.

Case No. ID 117/1993

Sh. Sardari Lal C/o President,
Nangal Bhakra Mazdoor Sangh,
Nangal Township, District Ropar. ... Applicant

Versus

The Chief Engineer, BBMB,
Nangal Township, District Ropar ... Respondent

APPEARANCES

For the Workman : Shri R. K. Singh
For the Management : Shri Bhagat Singh

AWARD

Passed on 13-8-08

Ministry of Labour, Government of India vide Notification No. L-420/12/80/92 IR-(DU) dated 29-9-93 referred the following industrial dispute for judicial adjudication :

"Whether the decision of the management of B.B.M.B. communicated to Shri Sardari Lal in compliance with the directions of the High Court of Punjab and Haryana dated 6-11-90 in Civil Writ Petition No.14026/90 is legally justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

As per the statement of claim, the workman, an ex-serviceman of the Indian Army and had served the same for about 15 years as Wireless Operator, was employed by the management of respondent as Wireless Operator in the year 1982 in the Hydrology Division and was deputed to work on specified period in every rainy season till 1989.

As per the policy decision of the management, the management had taken some persons on daily-wages as Wireless Operators. The persons who were taken as Wireless Operators on daily-wages are Shri Vidya Dass, Shri Sarup Chand and Shri Arjun Singh posted at Sunni, Sunder Nagar and Dalli respectively, since July, 1989 on regular basis, irrespective of the fact, that all these persons named above were junior to him. No retainership allowance was given for the period in which petitioner was put to idleness after the expiry of every rainy season. Shri Sarup Chand was appointed even though he was not having the required qualification and was over-aged and the name of the workman was not considered which is unfair labour practices. The workman had made number of representations to the management of respondent for regularization of his services and the last representation by Registered A.D. was sent to the management on 4-1-90. Therefore, regularization in service is prayed by the workman.

Apart from the objections on merit few preliminary objections were, raised by the management. Considering the nature of the preliminary objections raised and on the basis of the fact that these preliminary objections were not pressed, thereafter, I am not mentioning the preliminary objections. It has been stated by the management of respondent in written Statement that except for the monsoon season of 1983, as the workman did not appear for the interview, he was given a regular work in the year 1982, and from 1984 to 1990. The selection was based on the interview every year and the appointment was given for specified period during monsoon season in these years. Management denied that any person junior to him was appointed on the regular basis against the permanent vacancies. In the year 1988, all the 4 persons namely Vidya Dass, Arjun Singh, Sarup Singh and Sardari Lal were selected for the monsoon season and all were informed to join on 9.7.98 telegraphically. Shri Vidya Das joined on 9-7-88, Shri Arjun Singh joined on 10-7-88, Shri Sarup Singh joined on 11-7-88 and the workman Shri Sardari Lal joined on 13-7-88. Thus, on the basis of the date of joining Sardari Lal, the workman was junior to all the three persons named above. As per the policy letter No. 30315-450-PD/468/87-A

dated 8-7-88 affirmed compliance of directions of Hon'ble the High Court given in Civil Writ Petition No. 27/88, Smt. Ram Piani and Others vs. B.B.M.B., the workman is junior to all the three above named persons. Hon'ble the Supreme Court of India in Civil Appeal No. 5635/90 declined to intervene in the policy instructions made by the management of B.B.M.B. The workmen were appointed for the short period, therefore, there is no question in the payment of retainerhip allowance.

From the pleadings of parties, it is also evident that before this reference, Shri Sardari Lal raised a demand notice and during the conciliation proceedings before ALC, Chandigarh, he withdrew the demand notice and filed a writ petition titled as Writ Petition No. 14026/90 before Punjab and Haryana High Court. The Division Bench of Punjab and Haryana High Court on 5-11-90 passed the following order:—

"After hearing the learned counsel for the petitioner and the representation made by the petitioner in the form of application dated 28-3-88 (Annexure P-3), Annexure P-4 and dated 14-1-90 (Annexure P-5) have not been considered by the respondents order. The respondents are directed to examine the contentions made by the petitioner in the aforesaid representations and decided the same in accordance with law by passing a speaking order within 3 months. Petition stands disposed of."

On perusal of the materials on record, it is also evident that the representations of workman Shri Sardari Lal were considered and examined as per law, policy instructions of the management and a self contained speaking order was passed vide letter No. 118-2/HYD dated 23-1-91 rejecting to the claims of the workman. The decision of Executive Engineer dated 23-1-91 was conveyed to the workman. Thereafter, the workman again raised the industrial dispute which was referred by Ministry of Labour, Government of India to this Tribunal for judicial adjudication on account of the failure of the conciliation proceedings.

The main question for determination before this Tribunal is whether the management of the respondent has rightly rejected the contentions of workman made by him in two representations. The claim of the workman is that the services of 3 juniors were regularized and he was denied for the regularization. The management had disputed this contention by saying that all the 3 persons named by the workman are senior to him as per the seniority list available on record. I have gone through the Seniority List which was prepared by the management of respondent in compliance of the order of the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana given in Civil Writ Petition No. 27/88, Smt. Ram Piani and Others vs. B.B.M.B. The seniority list prepared by the management under directions of Hon'ble the High Court of Punjab and Haryana was not interfered by the Supreme Court in Civil Appeal No. 5935/90 and

accordingly the seniority list prepared as per the Board Policy No. 3031-450/PD-468/87-A dated 8-7-88 becomes final. As per the seniority list, the 3 persons named by the workman in his statement of claim namely Shri Vidya Dass, Shri Arjun Singh and Shri Sarup Singh are senior to Sardari Lal, the workman in present case. The management of respondent has also shown the cause of juniority of Shri Sardari Lal as he joined on 13-7-88 whereas, the above named persons have joined earlier to 13-7-88. Thus, on the basis of the policy decision taken by the management of respondent which was in compliance of the direction of Hon'ble the High Court and was approved by the Hon'ble Supreme Court of India, no discretion or regularization of the services is made by the management. Apart from this, the regularization of the workman on any other ground cannot be considered by this Tribunal because of the directions of Hon'ble Apex Court in Uma Devi's case (Secretary, State of Karnataka vs Uma Devi 2006 SCT 462).

Accordingly, the management of the respondent has rightly disposed of the representations of the workman with the right finding declining the prayer of the workman and the workman is not entitled to any relief. The reference is answered accordingly. Let Central Government be informed. File be consigned.

Chandigarh

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2008

का. आ. 2718. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूचना में केन्द्रीय सरकार में बी.बी.एम.बी. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, श्रम न्यायलय, नं. 1, चण्डीगढ़ के पंचाद (संदर्भ सं. 145/91) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एन-2201/16/91-आई आर (डी.यू.)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 3rd September, 2008

S.O. 2718. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (11 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 145/91) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. 1, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. BBMB and their workman, which was received by the Central Government on 3-9-2008.

[No.L-42011-16-91-IR(DU)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRIGYANENDRAKUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1,
CHANDIGARH**

Case No. ID 145/1993

Sh. Satpal Shah, General Secretary, B.B.M.B. Karamchari
Sangh, Nangal Township, Distt. Ropar (Punjab)-140124.

....Applicant

Versus

The Chief Engineer, Bhakra Dam, Bhakra Beas
Management Board, Nangal Township, Distt. Ropar (Pb.)-
140124.

....Respondent

APPEARANCES

For the workman : Shri R. K. Singh

For the management : Shri Bhagat Singh

AWARD

Passed on 12-8-08

Central Government vide notification no. L-420 11/
16/91-IR(D.U.) dated 8-10-91, referred the following
industrial dispute for judicial adjudication to this
Tribunal:—

“Whether the action of the Chief Engineer, Bhakra
Dam, B.B.M.B. Nangal Township in declining to
give pay protection to the workmen (as per annexure)
is justified? If not, to what relief the concerned
workmen are entitled?”

As per the pleadings of the parties, all of the workmen
named in the annexure list to the reference, which are 18 in
No. are retrenched of Beas Dam BSL project. Out of the
above workmen, the workmen mentioned at serial No. 1-11
were re-employed in B.R.S. division whereas, the workmen
mentioned from serial No. 12-17 were re-employed in the
Bhakra Mechanical Division and the last workmen
mentioned at serial no. 18 was re-employed in the Bhakra
Dam, Division Nangal by the Chief Engineer, Bhakra Dam.
It was the fresh appointment of the workmen and the benefit
vide letter No. 5259-61/BMB/1713/46/SUB, dated 13-5-76
regarding the increments to retrenched employees was
given to all the workmen at the time of their fresh
appointment. All the workmen accepted the benefit of
increments and after their appointment raised the industrial
dispute for the protection of the salary of basic pay which
they were getting at the time of their retrenchment from
previous assignment.

All the workmen filed the affidavits and they were
cross-examined by the learned legal advisor of the
management of B.B.M.B. Almost all the workmen have

accepted that for the reappointment of the retrenched, there
is a scheme for awarding the increments and their pay had
been fixed in accordance with the, said policy. The main
question for the determination of this Tribunal is whether
the workman is entitled for their protection of pay on fresh
appointment to the B.B.M.B. by the Chief-Engineer?

It is true that all the employees were fixed to the
lesser basic pay as compared from the basic pay they were
getting in their previous assignment at the time of their
retrenchment. But as stated earlier that their appointment
is fresh in the different capacity and as per the policy of the
B.B.M.B., which is accepted by all the workmen, they were
given the benefit of the fixation of pay by giving some
additional increments on the length of service. As per the
letter dated 13-5-76, which is the also decision of the
B.B.M.B. for every retrenched on his re-appointment one
increment will be given for two years services in the
department from which he was retrenched subject to the
five maximum increments. As per this policy decision, the
pay of all the workmen was fixed and accepted by the
workmen. Now, it is not open to them to re-open the matter
once again for fixation of the salary on the basis of the
basic pay scale they were drawing in the previous
department at the time of their retrenchment. The
appointment of all the workmen is fresh. They have been
given the benefit of the increments as per the above policy
of B.B.M.B. and all the workmen have received the
retrenchment compensation from the department, they were
retrenched. Accordingly, this reference is answered
positively that the action of the Chief Engineer, Bhakra
Dam, B.B.M.B., Nangal Township in declining to give
pay protection to the workmen (as per annexure) is justified
and the workmen are not entitled to any relief. Let the
Central Government be informed. File is consigned.

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2008

का. आ. 2719,—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
(1947 का 14) को धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार जवाहर
नवोदय विद्यालय के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों
के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार
औद्योगिक अधिकरण/ग्राम न्यायलय नं. 1, चण्डीगढ़ के पंचाट
(संदर्भ सं 17/95) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को
3-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-42012/66/94-आई.आर.(डी.यू.)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 3rd September, 2008

S.O. 2719.—In pursuance of Section 17 of the
Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 17/95)
of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour

Court, No. 1, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Jawahar Navodaya Vidyalaya and their workman, which was received by the Central Government on 3-9-2008.

[No. L-42012/66/94-IR(DU)
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1,
CHANDIGARH**

Case No. ID 17/1995

Sh. Subey Singh S/o Sh. Harinder Kumar,
Advocate District Court, Bhiwani-125036Applicant

Versus

The Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya,
Devrala, District-BhiwaniRespondent

APPEARANCES

For the Workman : Sri Sagir Ahmed

For the management : Sri Sandeep Bhardwaj

AWARD

Passed on 13-8-2008

Central Government vide notification No. L-42012/66/94-IR(D U.) dated 22-2-95, referred the following industrial dispute for judicial adjudication to this Tribunal:

"Whether the action of the management of Jawahar Navodaya Vidyalaya in terminating the service of Shri Subey Singh ex-group 'D' daily paid employee w.e.f. 15-12-92 just, fair and legal? If not, what relief he is entitled to and from what date?"

The contention of the workman is that he was appointed by the Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Devrala on the post of group 'D' w.e.f. 12-4-91 and he was assigned the duties of Plumber, Mess-helper and Peon-cum-Chowkidar. He was appointed through Employment Exchange, Haryana on daily wages and he continued to work up to 15-12-92, and thus, he has completed more than 240 days service without any break. The Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya terminated his services on 15-12-92 without notice or retrenchment compensation for which he raised an industrial dispute before R.L.C. and on failure of conciliation proceedings the above mentioned reference was referred to this Tribunal by Central Government for judicial adjudication.

Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Devrala, Bhiwani opposed the reference by filing written statement.

He raised certain preliminary objections which were not pressed thereafter. On merits, it has been stated by the Principal, Navodaya Vidyalaya, Devrala that the workman was appointed on 12-4-91 against a temporary vacancy of daily wager for a limited period for casual work. The Government sanction two daily wager post for Kendriya Vidyalaya which were withdrawn and accordingly the workman was relieved. The workman has not work for 240 days continuously in the preceding year from the date of his termination and accordingly was not entitled to any relief in terms of the reference.

Opportunity for adducing evidence was given to both of the parties. The workman filed his affidavit and was cross-examined by learned counsel for the Kendriya Vidyalaya and, accordingly, Principal Kendriya Vidyalaya filed his affidavit and was cross-examined in detail by learned counsel for the workman.

Certain documents have been filed by the workman. Order dated 12-4-91 which is the appointment letter of Shri Subey Singh, workman is on record. Relieving order 15-12-92 is also on record. These letters are Ex. W.2 and W.3 respectively. Ex. W.4 is the letter written by the Principal Jawahar Navodaya Vidyalaya, Devrala on 10-12-92 to the Deputy Director Navodaya Vidyalaya Samiti, Regional Office Jaipur asking him to sanction one post of group "D" employee under General category to adjust the services of Shri Subey Singh. In his letter the Principal of Kendriya Vidyalaya has mentioned the dates on which he has worked and regarding the work and conduct of the workman. Another letter Ex. W.5 is written by Principal Jawahar Navodaya Vidyalaya, Devrala to the Deputy Director, Navodaya Vidyalaya Samiti, Jaipur on 9-12-92 with the same request for sanctioning one group "D" post for adjustment of Shri Subey Singh.

Another letter dated 12-12-92 written by the Principal Jawahar Navodaya Vidyalaya to the Deputy Director, Jaipur is on record as Ex. W.6 containing the same request for sanctioning group D post in General Category for adjustment of the workman Shri. Subey Singh. It is a detailed letter which reflects the nature behavior and attitude of the workman while he served the Vidyalaya. Ex. W. 7 is the relieving order of the workman dated 30-6-92 Ex. W. 8 is the appointment letter from 4-8-92 given by Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Devrala, Ex. W.9 & W. 10 are also the letter written by Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya to the Deputy Director, Navodaya Vidyalaya Samiti, Jaipur on 7-10-93 and 1-11-92 respectively.

Learned counsel for the management has filed the written arguments as well. Opportunity for oral arguments was given to the parties. The main contention of learned counsel for the management is that when the workman sought the regularization of the service he was over-aged. Thus, being over-aged his case was not rightly considered and accordingly he was terminated from the service. Learned counsel for the management has relied upon a case law

published in 2007(2) Supreme Court Cases (L&S) 534 Trimbal Triupati Devasthanams Vs. K. Jyothswarra Pillai and another. This is the law on the relaxation of the age and learned counsel for the management has rightly said that in para no. 7 of the claim statement Shri Subey Singh has mentioned that he was over-aged and he cannot sought regularization of his services. In this regard, I will prefer to mention that the question for adjudication before this Tribunal is not regarding the regularization of the services of the workman but to hold whether his termination from the services is legal and justified. There is no iota of evidence on record that at the time of his initial appointment to Jawahar Navodaya Vidyalaya, the workman was over-aged and his initial appointment was not valid. Accordingly the case law referred by learned counsel is not applicable in the instant case.

Learned counsel for the management has also relied upon a case law published in 2008(1) Supreme Court Cases 683 Additional Manager, Aravali Golf Club and another Vs. Chandarhass and another, which is on creation of post. It has been held by the Hon'ble the Apex Court that creation of and sanction of posts is the prerogative to the Legislative Authority and not of the Courts. Again the question before this Tribunal is not for creation of posts but for the justification of the termination of the workman. Accordingly, this case law is not applicable in the instant case. The another case law relied upon by the learned counsel of the management is Bala Krishna Behera and another Vs. Satya Parkash Dass, which is on the power of the High Court by the writ of mandamus to direct the appointment of a person against the post which has been abolished. Again the question before this Tribunal is regarding the justification of the termination order and the case law referred by the learned counsel for the management is not applicable. In Krishana Bhagya Jal Nigam Limited Vs. Mohamad Rafi 2007(1) SCC (L&S) 679 Hon'ble Supreme Court has held that the burden of proof lies on the workman to prove that he has work continuously for 240 days in the preceding year from the date of his termination and he was paid the wages for 240 days he worked.

Accordingly, the workman has to prove that he has worked for 240 days continuously in the preceding year from the date of his termination and he was paid wages for that period.

From the pleadings of the parties and the affidavit they filed, it is clear that the workman Shri Subey Singh was appointed vide Ex. W.2 on 12-4-91 on daily wages at the rates prescribed by Deputy Commissioner w.e.f. 12-4-91 and the wages were to be paid for the days of duty only and not on the monthly basis. The wages were paid on the days he worked is explained by the Principal, Navodaya Vidyalaya in his cross-examination on 13-9-2006 that the payment to the workman used to be given after completion of month. Thus, as per the evidence of Shri Ompal Thomar, Principal Incharge of Jawahar Navodaya Vidyalaya and the appointment letter

dated 12-4-91, the workman was paid for the days he worked but the mode of payment was monthly. From Exs. 4, 5, 6, 7 & 8 which are the original letters filed by the workman, it is clear that the workman worked from 12-4-91 to 30-6-92. He was again re-appointed on 1-7-92 and worked up to 13-8-92. Meaning thereby, there was no break in his subsequent appointment. Thereafter, he was further re-appointed on 14-8-92, though he resumed duty on 17-8-92 and worked up to 15-12-92, when he was relieved from the duties by Principal Jawahar Navodaya Vidyalaya, Devrala, vide letter dated 15-12-92 Ex. W.2.

There is one more contention of learned counsel for the management that the M.W. 1 has categorically stated in his evidence that in summer and winter breaks Shri Subey Singh had not worked. I am unable to accept this contention of the management because the vary letters of the management which are filed by the workman shows that the workman was working in mid December and on 19-6-92. Ex. W7 is the relieving order given by the Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Devrala containing the contents that Shri Subey Singh was engaged on daily wages in this Vidyalaya on 12-4-91(F.N.) and was relieved w.e.f. 30-6-92 (A.N). Month of June is the period of summer vacations on which as per the relieving order given by the management, the workman has worked.

It is true that workman has to prove that he had worked continuously for 240 days preceding the date of his terminating and was paid the wages for 240 days accordingly. The statement in the statement of claim and in affidavit will not be sufficient but the workman has to prove the above facts by some cogent evidence. The workman accordingly has filed the original documents to prove this fact.

From the perusal of the record, it is established that initial appointment of the workman was proper. It has not been challenged by the management that the initial appointment of the workman was not regular. He worked continuously from 14-4-91 to 30-6-92 except three days breaks of 14-8-92, 15-8-92 and 16-8-92. Accordingly the total working days comes to 480 days approximately. As per the evidence of the management the workman was paid monthly but on the basis of dates he worked. Accordingly, as per the policy Sundays and Holidays are to be counted while calculating the working days. The workman was released on 30-6-92 and preceding to the year from the date of his termination, he has completed 240 days continuously and was paid there off.

He was retrenched without any notice or retrenchment compensation. Thus, his termination is illegal in the eyes of law.

Now the question is what relief should be given to the workman? As per the statement of the witness of the management, the workman was relieved from the service because, there was no vacancy. There were two vacancies for the casual labour which were taken away by the

Government. Thus, the direction for reinstatement into service will not be possible as there is no post and as per the law laid down by the Hon'ble Apex Court in Divisional Manager, Aravali Golf Club and another Vs. Chandarhass and another (supra) it is not within the preview of the Tribunal to direct for the creation of the posts. In such the cases, the Tribunal should award the compensation on reasonable cases and this Tribunal is authorized to do so. The reasonable bases for awarding the compensation includes the amount of retrenchment compensation which would have been given by the management to the workman at the time of his relieving from the services, depreciation in money from the date of removal from the service till the payment of compensation, interest on the amount and the litigation expenses incurred by the workman for the wrongful act of the management. Considering the above facts as the workman has stated in his cross-examination that at the time of his removal from the service he used to get Rs. 835 p.m. and considering all the facts mentioned above, Rs. 25,000 will be the appropriate compensation to be given to the workman. Accordingly, this reference is answered in negative that the action of the management of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Devrala in terminating the services of Shri Subey Singh ex-group D daily paid employee w.e.f. 15-12-1992 is not just fair and legal. The workman is entitled for the compensation of Rs. 25,000 from the management. Management is accordingly directed to pay Rs. 25,000 within a month. Let the Central Government be informed. File is consigned.

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का. आ. 2720. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एस.सी. सी.एल. के प्रबंधन के संबंध निर्योजकों और उनके कार्यकर्ताओं के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ सं 78/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/11/2006-आई आर(सीएम-1)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2720.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 78/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad now as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited and their workmen which was received by the Central Government on 4-9-2008.

[No. J-22012/11/2006-IR(CM-II)]
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT HYDERABAD

Present : Shri VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Dated the 18th day of August, 2008

INDUSTRIAL DISPUTE NO. I.D.78/2006

BETWEEN

The General Secretary,
(Sri Bandari Satyanarayana)
Singareni Collieries Employees Council,
H.No.18-3-90/3, Ganesh Nagar,
Markandeya Colony,
Godavarikhani-505209. .. Petitioner

AND

The General Manager,
M/s. Singareni Collieries Company Limited
Mandamarri Division,
Mandamarri-504231 ... Respondent

APPEARANCES

For the Petitioner : NIL
For the Respondent : M/s. P.A.V.V.S. Sama &
Vijaya Laxmi Panguluri,
Advocates

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. J-22012/11/2006-IR(CM-II) dated 23-10-2006 referred the following dispute between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workman under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the action the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri Pannala Jayalath w.e.f. 28-2-2000 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case is called out several times after repeated intervals. None appeared for Petitioner. Respondent's representative present. Petitioner has not submitted his claim statement although several opportunities has been given to him. He is absent today also. No application for adjournment has been filed. As such, it appears that the Petitioner is not interested to pursue this case.

3. Accordingly, this case is being closed and this Court is of view that the Petitioner deserves no relief in respect of the matter in reference. Hence, "NIL" Award is passed.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 28th day of August, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner Witnesses examined for the Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का. आ. 2721.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एस.सी. सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोक्तों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 77/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/12/2006-आई आर (सीएम-II)]
अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2721.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 77/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad now as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on 4-9-2008.

[No. L-22012/12/2006-IR(CM-II)]
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT HYDERABAD

Present : Shri VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Dated the 18th day of August, 2008

INDUSTRIAL DISPUTE NO. I.D. 77/2006

BETWEEN

The General Secretary,
(Sri Bandari Satyanarayana)
Singareni Collieries Employees Council,

H.No.18-3-90/3, Ganesh Nagar,
Markandeya Colony,
Godavari Khani-505209

... Petitioner

AND

The General Manager,
M/s. Singareni Collieries Company Limited
Mandamarri Division,
Mandamarri-504231

.. Respondent

APPEARANCES

For the Petitioner : NIL

For the Respondent : M/s. P.A.V.V.S. Sarma &
Vijaya Laxmi Panguluri,
Advocates

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-22012/12/2006-IR(CM.II) dated 23-10-2006 referred the following dispute between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workman under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the action the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri Bhukya Pantulu w.c.f. 18-2-1999 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case is called out several times after repeated intervals. None appeared for Petitioner. Respondent's representative present. Petitioner has not submitted his claim statement although several opportunities has been given to him. He is absent today also. No application for adjournment has been filed. As such, it appears that the Petitioner is not interested to pursue this case.

3. Accordingly, this case is being closed and this Court is of view that the Petitioner deserves no relief in respect of the matter in reference. Hence, 'NIL' Award is passed.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 18th day of August, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner Witnesses examined for the Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

(सि. एल. 2723/2008)

का. आ. 2723, अर्थात् 1999 का अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसार में केंद्रीय सरकार एस.सी. सी.एल. के प्रबंधन के संबंध में कार्यकर्ताओं और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध निरिष्ट औद्योगिक विवाद में केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के संघर्ष में 26/2006) को प्रकाशित करने के लिए संघर्ष का 2008 का प्रकाशित हुआ था।

(सि. एल. 2723/2008-आई आर सीएस 111)

अनवर कुमार मोहम्मद खान

Sd/- (Sd/-) 18th September 2008

341 - 2723 - In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby transmits the award (Ref. No. 75/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited and their workmen, which was referred by the Central Government on 26/2/2006.

(सि. एल. 2723/2006-आई आर सीएस 111)
अनवर कुमार मोहम्मद खान

ANSWER

For the GOVERNMENT
Sd/- (Sd/-) 18th September 2008
VED PRAKASH GADGIL

President, State Industrial Tribunal, Presiding Officer

Date: 18th September 2008

(सि. एल. 2723/2006-आई आर सीएस 111)

(सि. एल. 2723)

The General Secretary
(Sri Bandari Srinivasulu Reddy,
Singareni Collieries Employees' Council,
H.No. 48-1/907, Cross 50 Nagar,
Markandeya Colony,
GodavariKonda-501316), Petitioner

AND

The General Manager
M/s. Singareni Collieries Company Limited,
Mandamari Division,
Mandamari-501251, Respondent

APPENDANT

For the Petitioner - NIL

For the Respondent - M/s. V.A.V.S. Sannaiah
Vengal Rao Sannaiah,
Advocate

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-22012-46/2006-IR(CM-II) dated 23-10-2006 referred the following dispute between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workmen under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is:

SCOPE OF

"Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri Gajjala Shankar w.e.f. 18-2-1999 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case is called out several times after repeated intervals. None appeared for Petitioner. Respondent's representative present. Petitioner has not submitted his claim statement although several opportunities has been given to him. He is absent today also. No application for adjournment has been filed. As such, it appears that the Petitioner is not interested to pursue this case.

3. Accordingly, this case is being closed and this Court is of view that the Petitioner deserves no relief in respect of the matter in reference. Hence, "NIL" Award is passed.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 18th day of August, 2008.

VED PRAKASH GADGIL, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner

NIL

Witnesses examined for the Respondent

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

18th दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2008

का. आ. 2723, अर्थात् 1999 का अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसार में केंद्रीय सरकार एस.सी. सी.एल. के प्रबंधन के संबंध में कार्यकर्ताओं और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध निरिष्ट औद्योगिक विवाद में केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के संघर्ष में 26/2006) को प्रकाशित करने के लिए संघर्ष का 2008 का प्रकाशित हुआ था।

(सि. एल. 2723/2008-आई आर सीएस 111)

अनवर कुमार मोहम्मद खान

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2723.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 76/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on 4-9-2008.

[No. L-22012/49/2006-IR(CM-II)]
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR
COURT AT HYDERABAD**

Present: Shri VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Dated the 18th day of August, 2008

INDUSTRIAL DISPUTE No. I.D. 76/2006**BETWEEN**

The General Secretary
(Sri Bandari Satyanarayana)
Singareni Collieries Employees Council,
H.No.18-3-90/3, Ganesh Nagar
Markandeya Colony,
Godavarikhani-505209. ...Petitioner

AND

The General Manager,
M/s. Singareni Collieries Company Limited
Mandamarri Division,
Mandamarri-504231 ...Respondent

APPEARANCES

For the Petitioner : NIL
For the Respondent : M/s. P.A.V.V.S. Sarma &
Vijaya Laxmi Panguluri,
Advocates

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-22012/49/2006-IR(CM-II) dated 23-10-2006 referred the following dispute between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workman under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri Md. Allauddin w.e.f.

24-7-1998 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case is called out several times after repeated intervals. None appeared for Petitioner. Respondent's representative present. Petitioner has not submitted his claim statement although several opportunities has been given to him. He is absent today also. No application for adjournment has been filed. As such, it appears that the Petitioner is not interested to pursue this case.

3. Accordingly, his case is being closed and this Court is of view that the Petitioner deserves no relief in respect of the matter in reference. Hence, 'NIL' Award is passed.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 18th day of August, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner Witnesses examined for the Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का.आ. 2724.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसार मैं, केन्द्रीय सरकार भारत की सरकार के प्रबंधकों के संबद्ध नियोक्तों और उनके कर्मचारों के बीच संघर्ष में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 76/2006) को प्रकाशित करती हूँ जो केन्द्रीय सरकार को 4-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/21/2006-आई आर सी एस-II]
अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2724.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 73/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, and their workmen which was received by the Central Government on 4-9-2008.

[No. L-22012/21/2006-IR (CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD****Present : Shri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer**

Dated the 18th day of August, 2008

Industrial Dispute No. I.D.73/2006

BETWEEN

The General Secretary

(Sri Bandari Satyanarayana)

Singareni Collieries Employees Council,

H.No. 18-3-90/3, Ganesh Nagar

Markandeya Colony,

Godavarikhani-505209

... Petitioner

AND

The General Manager,

M/s. Singareni Collieries Company Limited,

'Mandamarri' Division,

Mandamarri-504231

... Respondent

APPEARANCES

For the Petitioner : NIL

For the Respondent : M/s. P.A.V.V. S. Sarma &
Vijaya Laxmi Panguluri,
Advocates.**AWARD**

The Government of India, Ministry of Labour, Order No. I-22012-21/2006-IR (CM-II), dated 23-10-2006 referred the following dispute between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workman under section 10 (1) (d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is:

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri Durgam Ramulu w.e.f. 16-12-1998 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case is called out several times after repeated intervals. None appeared for Petitioner. Respondent's representative present. Petitioner has not submitted his claim statement although several opportunities has been given to him. He is absent today also. No application for adjournment has been filed. As such, it appears that the Petitioner is not interested to pursue this case.

3. Accordingly, this case is being closed and this Court is of view that the Petitioner deserves no relief in respect of the matter in reference. Hence, 'Nil' Award is passed.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 18th day of August, 2008

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner NIL

Witnesses examined for the Respondent NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का.आ 2725.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस.सी.सी.एल. के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 74/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/47/2006-आई आर(सी एम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2725.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 74/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, and their workmen which was received by the Central Government on 4-9-2008.

[No. I-22012/47/2006-IR (CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT
AT HYDERABAD****Present : Shri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer.**

Dated the 18th day of August, 2008

Industrial Dispute No. I.D.74/2006

BETWEEN

The General Secretary

(Sri Bandari Satyanarayana)

Singareni Collieries Employees Council,

H.No. 18-3-90/3, Ganesh Nagar

Markandeya Colony,

Godavarikhani-505209

... Petitioner

AND

The General Manager,

M/s. Singareni Collieries Company Limited

Mandamarri Division,

Mandamarri-504231

... Respondent

APPEARANCES

For the Petitioner : NIL

For the Respondent: M/s. P.A.V. V. S. Sarma &
Vijaya Laxmi Panguluri,
Advocates.

AWARD

1. The Government of India, Ministry of Labour, Order No. L-22012/47/2006-IR (CM-II), dated 23-10-2006 referred the following dispute between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workman under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri Sandra Chandraiah w.e.f. 9-3-1999 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case is called out several times after repeated intervals. None appeared for Petitioner. Respondent's representative present. Petitioner has not submitted his claim statement although several opportunities has been given to him. He is absent today also. No application for adjournment has been filed. As such, it appears that the Petitioner is not interested to pursue this case.

3. Accordingly, this case is being closed and this Court is of view that the Petitioner deserves no relief in respect of the matter in reference. Hence, 'NIL' Award is passed.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 18th day of August, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner : NIL

Witnesses examined for the Respondent : NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का.आ. 2726.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस.सी.सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 72/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/18/2006-आई आर(सी एम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2726.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 72/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on 4-9-2008.

[No. L-22012/18/2006-IR (CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT HYDERABAD

Present : Shri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer

Dated the 18th day of August, 2008

Industrial Dispute No. I.D. 72/2006

BETWEEN

The General Secretary
(Sri Bandari Satyanarayana),
Singareni Collieries Employees Council,
H.No. 18-3-90/3, Ganesh Nagar
Markandeya Colony,
Godavari Khani-505209

.....Petitioner

AND

The General Manager,
M/s. Singareni Collieries Company Limited,
Mandamari Division,
Mandamari-504231

.....Respondent

APPEARANCES

For the Petitioner : NIL

For the Respondent : M/s. P. A. V. V. S. Sarma &
Vijaya Laxmi Panguluri,
Advocates.

AWARD

1. The Government of India, Ministry of Labour, Order No. L-22012/18/2006-IR (CM-II), dated 23-10-2006 referred the following dispute between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workman under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri Durgam Bhoomaiah w.e.f. 10-9-2001 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case is called out several times after repeated intervals. None appeared for Petitioner. Respondent's representative present. Petitioner has not submitted his claim statement although several opportunities has been given to him. He is absent today also. No application for adjournment has been filed. As such, it appears that the Petitioner is not interested to pursue this case.

3. Accordingly, this case is being closed and this Court is of view that the Petitioner deserves no relief in respect of the matter in reference. Hence, 'NIL' Award is passed.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 18th day of August, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner : NIL

Witnesses examined for the Respondent : NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का.आ. 2727.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसार में, केन्द्रीय सरकार एस.सी.सी.एल. के प्रबंधन के संबंध निवासियों और उनके कर्मचारों के बीच अन्तर्ग्रह में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अतिक्रमण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 79/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एड.: 22012/13/2006-आई अर(सी एम. 11)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2727.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 79/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, and their workman, which was received by the Central Government on 4-9-2008.

[No. L-22012/13-2006-IR (CM-11)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT HYDERABAD

Present : Shri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer

Dated the 18th day of August, 2008

Industrial Dispute No. L.D. 79/2006

BETWEEN

The General Secretary
(Sri Bandari Satyanarayana),
Singareni Collieries Employees Council,
H.No. 18-3-90/3, Ganesh Nagar,
Markandeya Colony,
Godavari Khani-505209

...Petitioner

AND

The General Manager,

M/s. Singareni Collieries Company Limited

Mandamari Division,

Mandamari-504231

...Respondent

APPEARANCES

For the Petitioner : NIL

For the Respondent : M/s. P.A.V.M. S. Sarma &
Vijaya Laxmi Panguluri,
Advocates.

AWARD

1. The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-22012/13-2006-IR (CM-11), dated 23-10-2006 referred the following dispute between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workman under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri Balya Balya w.c. 26-2-1998 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case is called out several times after repeated intervals. None appeared for Petitioner, Respondent's representative present. Petitioner has not submitted his claim statement although several opportunities has been given to him. He is absent today also. No application for adjournment has been filed. As such, it appears that the Petitioner is not interested to pursue this case.

3. Accordingly, this case is being closed and this Court is of view that the Petitioner deserves no relief in respect of the matter in reference. Hence, 'NIL' Award is passed.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 18th day of August, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner : NIL

Witnesses examined for the Respondent : NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का.आ. 2728.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसार में, केन्द्रीय सरकार एस.सी.सी.एल. के प्रबंधन के संबंध निवासियों और उनके कर्मचारों के बीच अन्तर्ग्रह में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अतिक्रमण,

हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 80/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/10/2006-आई आर(सी एम-11)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2728.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 80/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, and their workman, which was received by the Central Government on 4-9-2008.

[No. L-22012/10/2006-IR (CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
HYDERABAD**

PRESENT : Shri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer

Dated the 18th day of August, 2008

Industrial Dispute No. I.D.80/2006

BETWEEN

The General Secretary
(Sri Bandari Satyanarayana)
Singareni Collieries Employees Council,
H.No. 18-3-90/3, Ganesh Nagar
Markandeya Colony,
Godavari Khani-505209

... Petitioner

AND

The General Manager,
M/s. Singareni Collieries Company Limited
Mandamarri Division,
Mandamarri-504231

... Respondent

APPEARANCES

For the Petitioner : NIL

For the Respondent : M/s. P.A.V.V.S. Sarma &
Vijaya Laxmi Panguluri,
Advocates

AWARD

1. The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-22012/10/2006-IR (CM-II), dated 23-10-2006 referred the following dispute between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workman under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri Madoti Raju w.e.f.

9-10-1998 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case is called out several times after repeated intervals. None appeared for Petitioner. Respondent's representative present. Petitioner has not submitted his claim statement although several opportunities has been given to him. He is absent today also. No application for adjournment has been filed. As such, it appears that the Petitioner is not interested to pursue this case.

3. Accordingly, this case is being closed and this Court is of view that the Petitioner deserves no relief in respect of the matter in reference. Hence, "NIL" Award is passed.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 18th day of August, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner : NIL

Witnesses examined for the Respondent : NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का.आ 2729.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस.सी.सी.एल. के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 82/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/15/2006-आई आर(सी एम-11)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2729.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 82/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, and their workman, which was received by the Central Government on 4-9-2008.

[No. L-22012/15/2006-IR (CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer
ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
HYDERABAD**

Present : Shri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer.

Dated the 18th day of August, 2008

Industrial Dispute No. I.D. 82/2006

BETWEEN

The General Secretary
(Sri Bandari Satyanarayana)
Singareni Collieries Employees Council,
H.No. 18-3-90/3, Ganesh Nagar
Markandeya Colony,
Godavarikhani-505209

...Petitioner

AND

The General Manager,
M/s. Singareni Collieries Company Limited
Mandamarri Division,
Mandamarri-504231

...Respondent

APPEARANCES

For the Petitioner : NIL
For the Respondent : M/s. P.A.V.V. S. Sarma &
Vijaya Laxmi Panguluri,
Advocates

AWARD

1. The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-22012/15/2006-IR (CM-II), dated 23-10-2006 referred the following dispute between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workman under section 10 (1) (d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri Baneni Suryanarayana w.e.f. 27-9-2002 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case is called out several times after repeated intervals. None appeared for Petitioner. Respondent's representative present. Petitioner has not submitted his claim statement although several opportunities has been given to him. He is absent today also. No application for adjournment has been filed. As such, it appears that the Petitioner is not interested to pursue this case.

3. Accordingly, this case is being closed and this Court is of view that the Petitioner deserves no relief in respect of the matter in reference. Hence, 'NIL' Award is passed.

Dietated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 18th day of August, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner NIL
Witnesses examined for the Respondent NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का.आ. 2730.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस.सी.सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 66/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/318/2005-आई आर(सी एम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2730.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 66/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, and their workmen, which was received by the, Central Government on 4-9-2008.

[No. I-22012/318/2005-IR (CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
HYDERABAD**

PRESENT : Shri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer.

Dated the 18th day of August, 2008

Industrial Dispute No. I.D. 66/2006

BETWEEN

The General Secretary
(Sri Bandari Satyanarayana)
Singareni Collieries Employees Council,
H.No. 18-3-90/3, Ganesh Nagar
Markandeya Colony,
Godavarikhani-505209

Petitioner

AND

The General Manager,
M/s. Singareni Collieries Company Limited
Mandamarri Division,
Mandamarri-504231

...Respondent

APPEARANCES

For the Petitioner : NIL
For the Respondent : M/s. P.A.V.V. S. Sarma &
Vijaya Laxmi Panguluri,
Advocates

AWARD

1. The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-22012/318/2005-IR (CM-II), dated 9-10-2006 referred the following dispute between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workman under Section 10 (1) (d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri Thogari Venkati w.e.f. 26-9-2001 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case is called out several times after repeated intervals. None appeared for Petitioner. Respondent's representative present. Petitioner has not submitted his claim statement although several opportunities has been given to him. He is absent today also. No application for adjournment has been filed. As such, it appears that the Petitioner is not interested to pursue this case.

3. Accordingly, this case is being closed and this Court is of view that the Petitioner deserves no relief in respect of the matter in reference. Hence, 'NIL' Award is passed.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 18th day of August, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner NIL

Witnesses examined for the Respondent NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का.आ 2731.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस्.सी.सी.एल. के प्रबंधन के संवेदक नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 81/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/14/2006-आई आर(सी एम-11)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2731.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 81/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, and their workmen, which was received by the, Central Government on 4-9-2008.

[No. L-22012/14/2006-IR (CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR
COURT AT HYDERABAD**

PRESENT : Shri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer

Dated the 18th day of August, 2008

Industrial Dispute No. I.D. 81/2006

BETWEEN

The General Secretary,
(Sri Bandari Satyanarayana)
Singareni Collieries Employees Council,
H.No. 18-3-90/3, Ganesh Nagar,
Markandeya Colony,
Godavarikhani-505209

....Petitioner

AND

The General Manager,
M/s. Singareni Collieries Company Limited
Mandamarri Division,
Mandamarri- 504231

....Respondent

APPEARANCES

For the Petitioner : NIL

For the Respondent : M/s. P.A.V. V. S. Sarma &
Vijaya Laxmi Panguluri,
Advocates

AWARD

1. The Government of India, Ministry of Labour, Order No. L-22012/14/2006-IR (CM-II), dated 23-10-2006 referred the following dispute between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workman under section 10 (1) (d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri Dasari Srinivas w.e.f. 28-2-2000 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case is called out several times after repeated intervals. None appeared for Petitioner. Respondent's representative present. Petitioner has not submitted his claim statement although several opportunities has been given to him. He is absent today also. No application for adjournment has been filed. As such, it appears that the Petitioner is not interested to pursue this case.

3. Accordingly, this case is being closed and this Court is of view that the Petitioner deserves no relief in respect of the matter in reference. Hence, 'NIL' Award is passed.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 18th day of August, 2008

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner NIL

Witnesses examined for the Respondent NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2008

का. अ. 2732, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार केन्टोनमेंट बोर्ड के प्रबंधन के खंडे नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुग्रह में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायलय, पटना के पंचाट (संदर्भ सं. 91/2004) को प्रकाशित करते हैं, जो केन्द्रीय सरकार को 4-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-13011/1/2003-आईआर (सी.यू.)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2732 -- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 91/2004) of the Industrial Tribunal/Labour Court, Patna as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Cantonment Board and their workman, which was received by the Central Government on 4-9-2008.

[No. L-13011/1/2003-IR(DU)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL
TRIBUNAL SHRAM BHAWAN, BAILEY ROAD,
PATNA

Reference Case No. 91 of 2004

No. 16 (C) of 2004

Between the management of Cantonment Board, Danapur Cantonment and their workman Ram Swaroop, resident of village-Turhatoli, P.O. Danapur, Patna.

For the Management : Shri Satish Kumar Agarwal and
Shri Binay Kumar, Advocates.

For the Workman : Shri Rajesh Sahay, Advocate.

Present : Vasudeo Ram, Presiding Officer,
Industrial Tribunal, Patna

AWARD

Patna, dated the 27th August, 2008

By adjudication Order No. L-13011/1/2003 IR(DU), dated 6-7-2004 the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi under clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-Section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter called 'the Act' for brevity) referred the dispute between the management of Cantonment Board, Danapur Cantonment and their workman Ram Swaroop of Village-Turhatoli, P.O. Danapur, Patna to Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Dhanbad No. 2 for adjudication on the following :

"Whether the action of the management of Cantonment Board, Patna in not fixing the pay-scale of Shri Ram Swaroop, Assistant Pump Driver Grade II in the pay scale of Rs. 950-20-1150-25-1500 legal and justified? And further, whether this has led to wrong calculation of the pension and other retirement dues? If yes to what relief the retired workman Shri Ram Swaroop is entitled to?"

Subsequently vide order No. L-13011/1/2003 IR(DU), dated 17-8-2004 the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi transferred the Reference Case in this Tribunal to dispose of the same according to law.

2. The parties appeared on notice and filed the written statement and the statement of claim respectively. The case of the workman as made out in the statement of claim is that he was appointed on the post of Khalasi (Lower Grade servant) under the management of Cantonment Board, Danapur Cantonment on 1-11-1956. The workman was promoted to the post of Assistant Pump Driver on 4-12-1963 and he worked on that post till 22-5-1968 and thereafter he was reverted back to the post of Pump/Khalasi. Further, the contention of the workman is that he was promoted to the post of Assistant Pump Driver in the Scale of Rs. 375-480 on 25th July, 1986 whereas Shri Saryug Shah, an employee junior to him was given promotion in the scale of Rs. 480-680. The workman claimed the Scale of Rs. 480-680 w.e.f. 1986 but the management paid no heed to his representations. Further according to the workman the scale of Rs. 480-680 was made effective w.e.f. 1-3-1986 vide Bihar Government Finance Department Resolution No. 3 P.A. R. 1/86-2 WI-dated 20-1-1987. Again the said scale of Rs. 480-680 was revised to the scale of Rs. 950-1500 but the workman was not given the said scale. The workman was made to retire on 31-7-1992 after completion of the age of 58 years. The workman claims the benefit of scale Rs. 950-1500 besides other retiral benefits.

3. The contention of the management is that the workman Shri Ram Swaroop was appointed on 1-1-1956 in the pay scale of Rs. 17-25 per month as IVth grade employee. He was promoted as Assistant Pump Driver w.e.f. 1-12-1963 in the pay scale of Rs. 35-45-55 per month. The workman on completion of 10 years of service was given First Time Bound Promotion on the post of Pump Driver Grade II w.e.f. 1-1-1986. He was given 2nd Time Bound Promotion with effect from 1-4-1989 in the pay scale of Rs. 825-15-900-20-1200 with other allowances. The workman superannuated from service with effect from 31-7-1992 on the monthly salary of Rs. 1160. The management further contends that Saryug Sah was appointed directly on the post of Assistant Pump Driver on 31-12-1981 whereas workman Ram Swaroop was promoted from the post of khalasi to the post of Assistant Pump Driver in 1986. Further according to the management Finance Department Resolution dated 20-1-1987 will not

be applicable to the employees of Cantonment Board and as such the workman is not entitled to the salary of Rs. 480-680 with effect from 1-3-1986 as claimed by the workman.

4. Upon the pleadings of the parties and in view of the terms of reference the following points arise out for decision :

- (i) Whether the action of the management of Cantonment Board, Patna in not fixing the Pay Scale of Shri Ram Swaroop, Assistant Pump Driver Grade II in the Pay Scale of Rs. 950-20-1150-25-1500, legal and justified ?
- (ii) Whether the fixation of pay of Shri Ram Swaroop in the Scale of Rs. 950-1500 has led to wrong calculation of his pension and other retiral benefits ?
- (iii) What relief or reliefs Shri Ram Swaroop is entitled to ?

FINDINGS

Point Nos. (i) & (ii) :

5. Both the parties have adduced oral as well as documentary evidence in support of their respective contentions. The management has examined altogether three witnesses namely Brind Kishore (M.W.1), an Accountant in Cantonment Board, Nagendra Kumar Gupta (M.W.2), Cashier in Cantonment Board and Kamleshwar Pathak (M.W.3) a retired U.D.C. of Cantonment Board. The management has filed photocopy of provisional pension and Gratuity Form of the workman (Ext. M), photocopy of receipt (Exts. M/1 to M/5), of service book of workman (Ext. M/6) and photocopy of application for commutation of pension (Ext. M/7). As against that one Chhote Lal Paswan (W.W.1) retired Pump Khalasi of Cantonment Board besides Ram Swaroop (W.W.2) the workman has been examined on behalf of the workman. The workman has filed photocopy of order No. 127 dated 25-7-1986 (Ext. W) photocopy of application for commutation of pension (Ext. W/1), photo copy of decision of A.L.C. (Central), Patna dated 14-3-1974 (Ext. W/2) and photocopy of letter dated 12-1-1999 of Cantonment Executive Officer (Ext. W/3).

6. M.W. 1 has stated that the workman Ram Swaroop was appointed on 1-11-1956 on the post of Pump Khalasi, he was promoted in 1986 and retired in 1992. The said facts are not disputed facts. M.W.1 has further stated that the workman has been paid all his dues and nothing is left to be paid to him. In his cross-examination the workman has got exhibited his documents Exts. W and W/1. I may mention here that photocopy of application for commutation of pension has been filed by both the parties, it is Ext. W/1 on behalf of the workman and Ext. M/7 on behalf of the management but commutation of pension is not the issue before this Tribunal in reference for adjudication. M.W.2 has proved certain documents namely the copy of the

statement of provisional pension and gratuity (Ext. M/8), receipts of payment of provisional gratuity, earned leave encashment etc. to the workman (Ext. M/1 to Ext. M/5) and the photocopy of his service book (Ext. M/6) which are not disputed and hence do not require discussion in detail. M.W.2 has stated that the workman had raised the dispute before the Labour Court and the verdict given by the A.L.C. (Central), Patna-cum-Conciliation officer is Ext. W/2. M.W.3 has also stated that the workman has been given all the retiral benefits. The workman retired in 1992 at the age of 58; the retirement age was enhanced to 60 years in the year 2000.

7. W.W.1 has stated that he had seen Ram Swaroop working as Pump Khalasi, Ram Swaroop (W.W.2) has stated that he was appointed on 1-11-1956 on the post of Pump Khalasi and he was getting Rs. 40 as pay and allowances. He was promoted to the post of Assistant Pump Driver on 4-12-1963 but on 22-5-1968 he was reverted to the post of Pump Khalasi and his pay was also reduced to that of a Pump Khalasi. He raised the dispute before the Asst. Labour Commissioner (Central), Patna and on 14-3-1974 there was an agreement (Ext. W/2) according to which he should have been given the scale of Rs. 950-1500 but the management did not give the same. Accordingly, the workman claims scale of Rs. 950-1500 and other benefits on that scale. From perusal of Ext. W/2 it appears that the dispute with regard to reversion of workman Ram Swaroop was raised before the Labour Enforcement Officer (Central), Patna-cum-Conciliation Officer and the same terms of settlement that the management agreed to take necessary action to create an additional post of Asst. Pump Driver in its next Board meeting and to obtain sanction of the Central Command, Lucknow. It was also agreed that the case of Shri Ram Swaroop will be considered and priority will be given in the matter of regularisation to the cadre of Asst. Pump Driver. It was decided to implement the above agreement within three months. Nothing has been filed on behalf of the parties to show as to whether steps for implementation of the said agreement was taken and with what result. The workman in his statement before this Tribunal has stated that he was not given the scale as per agreement. The said Ext. W/2 does not show that it was an agreement for giving scale to the workman.

8. The workman claims that the scale of Rs. 950-1500 is the revised pay scale of Rs. 480-680. The workman in the statement of claim has claimed that Saryug Sah, an employee junior to him was given the scale of Rs. 480-680 but he being the senior in service to Shri Saryug Sah was given the scale of Rs. 375-480, but the workman in his statement before this Tribunal is silent on that point and has not whispered anything on that point. However, a photocopy of Order No. 127 dated 25-7-1986 has been filed on behalf of the workman and has been marked Ext. W from personal of which it appears that Shri Saryug Sah was in Pump Driver Grade II from 21-2-1981 and was promoted to Pump Driver

Grade I in the scale of Rs. 480-680 whereas this workman who was Pump Khalasi from 1-11-1956 was consequently promoted to Pump Driver Grade II in the scale of Rs. 375-480 in the vacancy caused by promotion of Shri Saryug Sah. I may mention here that the workman (W.W.?) in his statement before this Tribunal has stated that he was promoted to the post of Assistant Pump Driver on 4-12-1963 but he was reverted to the post of Pump Khalasi on 22-5-1968 and his pay was also reduced to that of Pump Khalasi. Under the circumstances I find that the workman cannot claim the scale of Rs. 480-680 consequently of Rs. 950-1500 on the basis of being senior to Shri Saryug Sah.

9. Both the parties have filed the copy of memorandum of settlement between the Cantonment Board and their workman 1969 (though not marked Exhibit) which are on record. Accordingly to para 7 of the said settlement "in the event of revision of pay scale by a state Government after 1-9-1996, the revised pay scale and the formula for fixation of pay in the revised pay scale as specified by the State Govt. shall, mutatis mutandis be made applicable to the Cantonment Board employees in the State Government employees." According to the said settlement (at serial No. 2) the existing designation of Asst. Pump Driver Pump Driver was proposed to be designated as Pump Driver Grade II which will be equivalent to Asst. Pump Mistri of Bihar Government and the same scale was to be given and the existing designation of Pump Driver (at serial No. 22 of memorandum) was proposed to be designated as Pump Driver Grade I which is equivalent to Truck Driver in Bihar Government photocopy of Bihar Gazette dated 14-2-1996 has been filed which shows that Truck Driver in Bihar Government (Pump Driver Grade I in Cantonment Board) has been given scale of Rs. 950-1500. Asst. Pump Driver Grade II under the circumstances can not claim that scale of Rs. 950-1500 as claimed by the workman. The workman has filed photocopy of letter dated 12-1-1999 of the Cantonment Executive Officer, Danapur Cantonment (Ext. W3) which shows that the Executive Officer mentioned that the Pump Driver Grade I and Pump Driver Grade II both are performing the same duties and requested that the sanction of GOC-in-Chief may be obtained to revise the pay scale of Pump Driver Grade II w.e.f. 1-1-1986. But nothing has been filed to show that the sanction as requested has been granted by the GO-in-Chief. Under the circumstances discussed above I find that the workman who retired as Asst. Pump Driver Grade II cannot claim the scale of Rs. 950-1500. Under the circumstances discussed above I find and hold that the action of the management of Cantonment Board, Patna in not fixing the pay scale of the workman in the scale of Rs. 950-1500 cannot be said illegal and unjustified. Accordingly I find and hold that non-fixation of pay of the workman in the scale of Rs. 950-1500 has not led to wrong calculation of his pension and other retiral benefits. Point Nos. (i) & (ii) are decided accordingly.

Point No. (iii) :

10. Keeping in view the discussions made above and the finding arrived at on Point Nos. (i) and (ii) I find and hold that the workman is not entitled to any relief claimed for. This point is decided accordingly.

11. Under the circumstances discussed above I find and hold that the action of the management of Cantonment Board, Patna in not fixing the pay scale of Shri Ram Swaroop, Assistant Pump Driver Grade II in the scale of Rs. 950-1500 is legal and justified. Further, I find that this has not led to wrong calculation of the pension and other retirement dues. I also find that retired workman Shri Ram Swaroop is not entitled to any relief.

12. And that is my award.

V. RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का. आ. 2733. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) को धारा 1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा संचार के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/क्षेत्र न्यायालय पुणे के पंचाट (संदर्भ सं.) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/23/2004-आईआर(पुणे)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2733. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal/Labour Court, Pune now as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 4-9-2008.

[No. L-40012/23/2004-IR(DU)]

ATAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, IN LABOUR COURT, PUNE AT PUNE

Reference (IDA) No. 650/2004

Esh. No. 31

Bharat Sanchar Nigam Limited

Bajirao Road, Pune - 410042

.. 1st Party

AND

Ramesh S. Khaladkar Post Nandgaon

Tal. Daund, Pune

.. 2nd Party

Coram : Shri P.T. Rahule

APPEARANCES: Mr. Zende - Advocate for 1 Party
Mr. A.Y. Shikarkhane - Adv (Ind Party)**AWARD**

dated the 25th April, 2008

This reference is made by Dy. Commissioner of Labour, Government of India, Bharat Sarkar, Ministry of Labour, Shram Mantralaya, New Delhi under section 10(1) and 12(5) read with section 2-A of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of industrial dispute between above referred parties regarding the reinstatement with full backwages and incidental benefits.

2. The case of second party in brief is that he was employed in telephone exchange at Nandgaon since 1998. His job was to rectify telephone and cable faults, dig trenches, climb telephone poles and work on telephone lines, to clean the office etc. He was working under the supervision and control of JTO, Kedgaon - Shri Tewari. He was paid wages by JTO on Form No. SE-17. His monthly wages were Rs. 1000. From 1-1-2000, his services were terminated without any notice and compensation by JTO. Some times his wages were paid in cash without taking his signatures on any paper. He approached to All India SC/ST Union and pursued his case for permanency. As a result, the Principal General Manager of the 1st Party directed his subordinate officers to send details of services record of the Second Party. On 3-1-2003, the concerned SDE sent the details of the service etc. of the Second Party to the General Manager. Meanwhile, this reference came to be sent to the Court wherein the Second Party submitted the claim with the prayer of reinstatement and consequential benefits from 1-1-2000.

3. The claim of the Second Party has been resisted by the First Party by filing written statement at Exh.7. The very employer-employee relationship has been denied by the First Party. It has been contended by the First Party that the Second Party was never in the employment of the First Party as alleged. With this, the entire claim has been denied by the First Party and prayed for rejection of the reference.

4. Considering the pleadings and averments, the following points sprout out for determination; the reasonings and findings thereon are as under :

POINTS**FINDINGS**

1. Whether there was employer-employee relationship between the Second Party and First Party as alleged ?
2. Whether the Second Party was illegally stopped by the First Party to be in the employment of the First Party w.e.f. 1-1-2000 ?

Yes

Yes

3. Whether the Second Party is entitled to the relief claimed ?

Yes

4. What Award ?

Allowed

REASONS

5. Point No. 1 : The Second Party - Ramesh Khaladkar has examined himself at Exh. 17 and three others witnesses - Namdev Laxman Bhame, Dattatray Baburao Bhujbal, and Uttam Dattooba Shelar at Exh. 24, 25, 26 respectively. On the other hand, the Respondent has examined solitary witness - Avinash Keshavrao Dorale at Exh.28. Any of the parties did not place his reliance on the documentary evidence.

6. It is evident from the testimony of the Second Party - Ramesh Khaladkar that since 6-5-1998, he was working with the department of telecommunication at Nangaon. His job was to connect and repair the telephone. He was doing the repair in of underground cables. He was also starting generator in the office. He was doing his duties under the instructions and directions of JTO who was paying him monthly salary of Rs. 1000 by taking signature on his diary till December, 2002. That time JTO was Dwahale and sub-divisional officer was Palewar. Suddenly, he was asked not to come on duty and stopped coming on duty without paying any compensation.

7. In cross examination, he admitted that any appointment letter was not given to him by the First Party. He also admitted that any document has not been produced on record to show that JTO - Tiwari has given him the job and salary. The suggestions of falsehood have been totally denied by this witness.

8. Mr. Namdev Laxman Bhame - retired employee of this First Party has corroborated the testimony of the Second Party by deposing that he was appointed in the year 1964 in the department of telecommunication and was working till 2000. In the year 1998-99, he was working as a Telephone Lineman at Nangaon Telephone Exchange, where the Second Party - Ramesh Khaladkar was working with him as a Helper. He specifically deposed that as a Helper. The Second Party was repairing telephones, removing faults of cables etc. He also deposed that the Second Party was working with him as a Helper for five months till he was transferred from Nangaon to Jejuri.

9. In cross-examination in respect of the Second Party only, the suggestion was put to this witness that he has deposed false that the Second Party was working with him for five months and the same came to be turned down by this witness. Any other adverse admission could not be extracted in the cross-examination from this witness.

10. The other witness Dattatray Bhujbal who is still in the employment of the First Party has also corroborated the testimony of both these witnesses No. 1 and 2. It is evident from his testimony that in December 1998, he was transferred to Nangaon Telephone Exchange as a telephone

lineman. The Second Party was working for finding the cables faults and repairing the same. He was working at Nangaon Telephone Exchange till 2000. He also turned down his suggestions of falsehood regarding the Second Party. He also admitted that he did not have any documentary evidence to show that the Second Party was working with him at Nangaon Telephone Exchange. Excepts the suggestion of falsehood, any favourable answers could not be extracted from this witness.

11. The fourth witness—Uttam Shelar has deposed that when he joined his duty in the year 1976 and was transferred to Nangaon Telephone Exchange as a phone mechanic. He was knowing Ramesh Khaladkar as a resident of Nangaon and specifically deposed that the Second Party had never worked with him in Nangaon Telephone Exchange. This witness has not at all been cross-examined by the First Party by declining to cross.

On going through the very precise testimony of this witness No. 4, it is clear that though he has deposed that the Second Party had never worked with him in Nangaon Telephone Exchange, he did not depose that the Second Party was not working with the First Party. Moreover, he has also not deposed the period in which he was working at Nangaon as a phone mechanic and hence, his testimony for want of particular details, cannot be considered against the Second Party. In these circumstances, the First Party was supposed to bring all the details of this witness about when he was working at Nangaon Telephone Exchange and whether in that relevant period, the Second Party was working or not. The First Party has chosen to decline to cross-examination.

12. Though any documentary evidence has not been produced on record from the side of the Second Party, his testimony has been rightly corroborated by the two witnesses, one of which is the ex-employee of the First Party and one is not presently in the employment of the First Party. Moreover, the testimony of the fourth witness—Uttam Shelar, though not supported the Second Party for want of any details cannot be considered even against this Second Party—Khaladkar.

13. On behalf of the First Party Avinash Dorale—the Divisional Engineer has been examined. It is evident from his testimony that as per the directions of his superior, he has come to depose on behalf of the First Party. Any payment was not made to the Second Party. As per the record, there is nothing to gather that he had ever worked with the First Party.

14. In cross-examination, he admitted that he has not produced any power of attorney or authority to depose on behalf of the First Party. Further, he admitted that some part time casual labours were working in Daund Division. He could not tell the rates or procedure to regularise the labours, but denied that the JTO used to make the payment to the part-time casual labours on vouchers. At the same time, he admitted that the JTO was having impressed

account but has deposed that the contract labours were paid by the respective contractors.

He admitted in the cross-examination that some casual workers were regularised in Daund Division by the First Party. He could not clarify by which mode those casual labours were regularised. Any documentary evidence has also not been adduced on behalf of the First Party.

15. The learned Advocate—Mr. A.Y. Shikarkhane, for the Second Party, has submitted that the Second Party has completed continuous 240 days in the employment of the First Party. But at the same time, while terminating his services, the compliance of Section 25-F was not done by the First Party by not paying any retrenchment compensation and hence, he be reinstated with continuity of service and full back wages.

Per contra, the learned Advocate—Mr. Zende, for the First Party, has submitted that the entire burden was on the Second Party to prove that he had worked with the First Party but for want of any documentary evidence, it could not be proved. He picked the admission given by the witness No. 2 in cross examination that he was the only employee working at Nangaon. He also submitted that JTO—Tiware had not been examined by the Second Party though he is still in the employment of the First Party. He placed his reliance on the cases of *Mukund Staff & Officers Association v/s. Mukund Limited* [2007 (6) ALL MR 312] and *Secretary, State of Karnataka and others v/s. Umadevi and others* (AIR 2006 Supreme Court 1806).

16. Having considered the submission tabled by both the sides, considering the ratio of the authority of *Mukund Staff Officers Association v/s. Mukund Limited* [2007 (6) ALL MR 312], it is clear that the burden is on the Second Party to establish it when the claim has been denied by the First Party. The sum and substance of the second authority relied upon by the First Party is that the temporary employees appointed in violation of the constitutional scheme do not have any legal right to be permanently absorbed in the employment. The facts of the instant case being absolutely different than that of the foregoing authority, it cannot be made applicable in the instant case because it has been nowhere taken the stand by the First Party about the appointment by violation of the constitutional scheme.

17. Having considered the foregoing discussions coupled with the corroborated testimony of the Second Party and failure on the part of the first party to adduce any adverse evidence, I dauntlessly reach the conclusion that the employer-employee relationship exists between the Second Party and First Party and as the compliance of Section 25-F was not done by the First Party at the time of termination of services, it is held that he was illegally terminated by the First Party. I therefore, answer this issue Nos. 1 and 2 accordingly.

18. **Issue No. 3 :** In view of the findings on the issue Nos. 1 and 2, keeping in view the facts and circumstances of the Second Party witness, so far as the retrenchment and continuity of service are concerned, the Second Party is

very much entitled to the reliefs claimed in that regard. However, in the entire evidence, as it has not been brought on record by the Second Party about his efforts to acquire any alternative gainful employment, there being no other option, the Second Party is not at all entitled to the relief of back wages as claimed. I, therefore, answer this issue No. 3 accordingly, and in the aftermath, pass following order :

ORDER

The reference is allowed. The First Party is directed to reinstate the Second Party with continuity of service as a full time casual labour in regular vacancy wherever it is available. The prayer of back wages is rejected. No order as to the cost.

Place : Pune

Date : 25-4-2008

P. T. RAHULE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का. आ. 2734.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार दूर संचार के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 255/99) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/214/1999-आईआर.(डी.यू.)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2734.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award Ref. No. 255/99 of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, No. 1, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 4-9-2008.

[No. L-40012/214/1999-IR(DU)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1
CHANDIGARH

Case No. I.D. 225/99

Sh. Sanjeev Kumar S/o Sh. Mahabir Singh, R/o 733/11,
Dairy, Rohtak-124001Applicant

Versus

The Distt. Manager, Telecom, Rohtak-124001.

.... Respondent

APPEARANCES

For the Workman: None

For the Management: None

AWARD

Passed on 20th August, 2008

Central Govt. vide notification No. L-40012/214/1999-IR(DU), dated 21-10-1999, has referred the following disputes to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Deptt. of Telecommunication, Rohtak in terminating the services of Sh. Sanjeev Kumar Driver w.e.f. 14-10-1996 is legal and justified? If not, to what relief he is entitled?"

2. No one is present, on behalf of workman. Learned representative of the management is also not present. Since morning this reference has been called number of times. At 10.45 am, it was ordered to be placed before this Tribunal once again at 2 p.m. It is 2.30 now and on repeated calls no one is present, in spite of having of full knowledge of the proceedings of this reference. The reference is as old as referred to this Tribunal in the year 1999. On repeated calls since morning no one is present. Accordingly, the reference is dismissed in default for non-prosecution. Central Government be informed accordingly. File to be consigned.

Chandigarh.

20-8-2008

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का. आ. 2735.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 429/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/363/2000-आईआर.(डी.यू.)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2735.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 429/2000) of the Central Govt. Industrial Tribunal cum Labour Court, No. 1, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 4-9-2008.

[No. L-40012/363/2000-IR(DU)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH****Case No. I.D. 429/2000**Sh. Rajinder Singh S/o Lal Chand, C/o Ashok Sharma,
279, Sector-3, Faridabad-121001

...Applicant

*Versus*The General Manager, Telephones, Sector-16,
Faridabad-121001

...Respondent

APPEARANCES

For the workman : None

For the management : None

AWARD

Passed on 20th August, 2008

Central Govt. vide notification No. L-40012/363/2000/
IR(DU), dated 31-10-2000, has referred the following
disputes to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Deptt. of Telecom in terminating the services of Sh. Rajinder Singh w.o.f. 6-10-1998 is just and legal? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. No one is present, on behalf of workman. Learned representative of the management is also not present. Since morning this reference has been called number of times. At 10.45 am, it was ordered to be placed before this Tribunal once again at 2 p.m. It is 2.30 now and on repeated calls no one is present, in spite of having of full knowledge of the proceedings of this reference. The reference is as old as referred to this Tribunal in the year 2000. On repeated calls since morning no one is present. Accordingly, the reference is dismissed in default for non-prosecution. Central Government be informed accordingly. File to be consigned. Chandigarh.

20-8-2008

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का. आ. 2736.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एम.सी. सी.एल. के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 43/2005) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/118/2004-आई.आर.(सी.एम.-II)]

अजय कुमार गौड़, डेप्टी अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2736. -In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 43/2005) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of Singareni Collieries Company Limited, and their workmen, received by the Central Government on 4-9-2008.

[No L-22012/118/2004-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD****Present : SHRIVED PRAKASH GAUR, Presiding Officer**

Dated the 26th day of August, 2008

Industrial Dispute No. I. D. 43/2005**BETWEEN**

The General Secretary, (Sh. G. Solomon), Singareni Collieries Mine Workers Union, Qtr. No. 703, Opp. Rythu Bazar, Godavarihani-505209.

...Petitioner

AND

The Chief General Manager, Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam—I Division
Godavarikhan-505209.

...Respondent

APPEARANCES

For the Petitioner : Nil.

For the Respondent : M/s. C. Vijay Shekar Reddy &
S. Vijay Venkatesh, Advocates

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-22012/118/2004-IR(CM-II) dated 11-5-2005 referred the following disputes between the management of the Singareni Collieries Company Limited and their workman under section 18(1)(a) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is :

SCHEDULE

"Whether the action of the Chief General Manager, M/s. Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam-I Division, Godavarikhan in terminating the services of Sh. Mekala Rama Rao, Ex. Coal Filler (IDK-I Incline, Ramagundam Division I, Godavarikhan) with effect from 9-7-2001 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case is called out several times after repeated intervals. None appeared for Petitioner. Respondent's representative present. Petitioner has not submitted his claim statement although several opportunities has been given to him. He is absent today also. No application for adjournment has been filed. As such, it appears that the Petitioner is not interested to pursue this case.

3. Accordingly, this case is being closed and this Court is of the view that the Petitioner deserves no relief in respect of the matter in reference. Hence, 'NIL' Award is passed.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 26th day of August, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner	Witnesses examined for the Respondent
NIL	NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

गई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का. आ. 2737,—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एस.सी. सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 84/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/17/2006-आई.आर. (सी.एस.-II)]
अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2737,—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 84/2006) of the Central Government Indus. Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, and their workmen, received by the Central Government on 4-9-2008.

[No. L-22012/17/2006-IR(CM-II)]
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT HYDERABAD

Present : SHRI VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Dated the 18th day of August, 2008

Industrial Dispute No. I. D. 84/2006

BETWEEN

The General Secretary, (Sh. Bandari Satyanarayana),
Singareni Collieries Employees Council, H. No. 18-3-90/3,
Ganesh Nagar Markandeya Colony, Godavari Khani
505209.Petitioner

AND

The General Manager, M/s. Singareni Collieries Company
Ltd. Mandamarri Division, Mandamarri 504231
....Respondent

APPEARANCES

For the Petitioner : NIL
For the Respondent : M/s. P.A.V.V.S. Sarma & Vijay
Laxmi Panguluri, Advocates

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-22012/17/2006/IR(CM.-II) dated 25-10-2006 referred the following dispute between the management of the Singareni Collieries Company Limited and their workman under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is ,

SCHEDULE

"Whether the action the Management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the service of Sri Nagavath Govindu w.e.f. 18-2-1999 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case is called out several times after repeated intervals. None appeared for Petitioner. Respondent's representative present. Petitioner has not submitted his claim statement although several opportunities has been given to him. He is absent today also. No application for adjournment has been filed. As such, it appears that the Petitioner is not interested to pursue this case.

3. Accordingly, this case is being closed and this Court is of the view that the Petitioner deserves no relief in respect of the matter in reference. Hence, 'NIL' Award is passed.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 18th day of August, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner Witnesses examined for the Respondent

NIL. NIL.

Documents marked for the Petitioner

NIL.

Documents marked for the Respondent

NIL.

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का. आ. 2738...औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) को धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एस.सी. सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 83/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/16/2006-आई.आर. (सी.एम.-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2738...In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 83/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, and their workmen, received by the Central Government on 4-9-2008.

[No. L-22012/16/2006-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD**

Present : SHRI VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Dated the 18th August, 2008

Industrial Dispute No. I. D. 83/2006

BETWEEN

The General Secretary, (Sh. Bandari Satyanarayana),
Singareni Collieries Employees Council, H. No. 18-3-90/3,
Ganesh Nagar Markandeya Colony, Godaverikhani
505209. ...Petitioner

AND

The General Manager, M/s. Singareni Collieries Company
Limited Mandamarri Division, Mandamarri 504231
...Respondent

APPEARANCES

For the Petitioner : NIL

For the Respondent : M/s. P.A.V.V.S. Sarma & Vijaya
Laxmi Panguluri, Advocates

AWARD

The Government of India Ministry of Labour by its order No. L-22012/16/2006/IR (CM.-II) dated 23-10-2006 referred the following dispute between the management of the Singareni Collieries Company Limited and their workman under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the action the Management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the service of Sri Sandra Rajam w.e.f. 16-4-1998 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case is called out several times after repeated intervals. None appeared for Petitioner. Respondent's representative present. Petitioner has not submitted his claim statement although several opportunities has been given to him. He is absent today also. No application for adjournment has been filed. As such, it appears that the Petitioner is not interested to pursue this case.

3. Accordingly, this case is being closed and this Court is of the view that the Petitioner deserves no relief in respect of the matter in reference. Hence, 'NIL' Award is passed.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 18th day of August, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner Witnesses examined for the Respondent

NIL NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL.

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का. आ. 2739.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एस. सी. सी. एल. के प्रबंधकों के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 44/2005) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/119/2004-आई आर(सीएम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2739.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. 44/2005) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad now as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Co. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 4-9-2008.

[No. L-22012/119/2004-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD**

Present : Shri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer

Dated the 26th day of August, 2008

Industrial Dispute No. I. D. 44/2005

BETWEEN

The General Secretary, (Sh.G. Solomon),
Singareni Collieries Mine Workers Union,
Qtr. No. 703, Opp. Rythu Bazar,
Godavarikhani - 505209

... Petitioner

AND

The Chief General Manager,,
Singareni Collieries Company Limited,
Ramagundam - I Division,
Godavarikhani - 505209

... Respondent

APPEARANCES

For the Petitioner : NIL

For the Respondent : M/s. C. Vijaya Shekar Reddy and
S. Vijay Venkatesh, Advocates**AWARD**

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-22012/119/2004-IR(CM-II) dated 24-5-2005 referred the following dispute between the management of the Singareni Collieries Company Limited and their workman

under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the action of the Chief General Manager, M/s. Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam-I Division, Godavarikhani in terminating the services of Sri Mardela Matiesham, Ex-Coal Filler, GDK-6 B Incline, Ramagundam Division-I, Godavarikhani with effect from 2-8-2002 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case is called out several times after repeated intervals. None appeared for Petitioner. Respondent's representative present. Petitioner has not submitted his claim statement although several opportunities has been given to him. He is absent today also. No application for adjournment has been filed. As such, it appears that the Petitioner is not interested to pursue this case.

3. Accordingly, this case is being closed and this Court is of the view that the Petitioner deserves no relief in respect of the matter in reference. Hence, 'NIL' Award is passed.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 26th day of August, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidenceWitnesses examined for
Petitioner

NIL

Witnesses examined for
Respondent

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का. आ. 2740.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एस. सी. सी. एल. के प्रबंधकों के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 65/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/316/2005-आई आर(सीएम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2740.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. 65/2006) of

the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Singareni Collieries Co. Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 4-9-2008.

[No. L-22012/316/2005-IR(CM-II)]
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT HYDERABAD

PRESENT : Shri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer

Dated the 18th day of August, 2008

Industrial Dispute No. I. D. 65/2006

BETWEEN

The General Secretary,
(Sri Bandari Satyanarayana)
Singareni Collieries Employees Council,
H.No.18-3-90/3, Ganesh Nagar
Markandeya Colony,
Godavarikhani-505209. ... Petitioner

AND

The General Manager,
M/s. Singareni Collieries
Company Limited,
Mandamarri Division,
Mandamarri-504231. ... Respondent

APPEARANCES

For the Petitioner : NIL

For the Respondent : M/s. P.A.V.V.S. Sarma and Vijaya
Laxmi Panguluri, Advocates

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-22012/316/2005-IR(CM-II) dated 9-10-2006 referred the following dispute between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workman under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri Naresh Kumar Kori w.e.f. 10-10-2002 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case is called out several times after repeated intervals. None appeared for Petitioner. Respondent's representative present. Petitioner has not submitted his claim statement although several opportunities has been given to him. He is absent today also. No application for adjournment has been filed. As such, it appears that the Petitioner is not interested to pursue this case.

3. Accordingly, this case is being closed and this Court is of the view that the Petitioner deserves no relief in respect of the matter in reference. Hence, 'NIL' Award is passed.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 18th day of August, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for Petitioner	Witnesses examined for Respondent
NIL	NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का. आ. 2741. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की भाग 17 के अनुसूचन में केन्द्रीय सरकार एस. सी. सी. एल. के प्रमुखता के संबंध निम्नलिखित और उनके कर्मचारों के बीच अनुबन्ध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद के पचाट (संदर्भ सं. 71/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार की 4-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल. 22012/316/2006-आईआर(सीएम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2741. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 71/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Singareni Collieries Co. Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 4-9-2008.

[No. L-22012/316/2005-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS- TRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT HYDERABAD

PRESENT : Shri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer

Dated the 18th day of August, 2008.

Industrial Dispute No. I. D. 71/2006

BETWEEN

The General Secretary,
(Sri Bandari Satyanarayana)
Singareni Collieries Employees Council,
H.No.18-3-90/3, Ganesh Nagar
Markandeya Colony,
Godavarikhani-505209. ... Petitioner

AND

The General Manager,
M/s. Singareni Collieries
Company Limited,
Mandamarri Division,
Mandamarri-504231.

..Respondent

APPEARANCES

For the Petitioner : NIL

For the Respondent : M/s. P.A.V.V.S. Sarma and Vijaya
Laxmi Panguluri, Advocates**AWARD**

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-22012/20/2006-IR(CM-II) dated 23-10-2006 referred the following dispute between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workman under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the action the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri Kunsoth Shankar w.e.f. 16-12-1998 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case is called out several times after repeated intervals. None appeared for Petitioner. Respondent's representative present. Petitioner has not submitted his claim statement although several opportunities has been given to him. He is absent today also. No application for adjournment has been filed. As such, it appears that the Petitioner is not interested to pursue this case.

3. Accordingly, this case is being closed and this Court is of view that the Petitioner deserves no relief in respect of the matter in reference. Hence, 'NIL' Award is passed.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant, transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 18th day of August, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidenceWitnesses examined for
the PetitionerWitnesses examined for
the Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का. आ. 2742.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
(1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार

एस. सी. सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 70/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार का 4-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/311/2005 आईआर (सीएम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2742.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 70/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Co. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 4-9-2008

[No. L-22012/311/2005-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS-
TRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD**

PRESENT : Shri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer

Dated the 18th day of August, 2008

Industrial Dispute No. I. D. 70/2006

BETWEEN

The General Secretary,
(Sri Bandari Satyanarayana)
Singareni Collieries Employees Council,
H.No.18-3-90/3, Ganesh Nagar
Markandeya Colony,
Godavari Khani-505209.

..Petitioner

AND

The General Manager,
M/s. Singareni Collieries
Company Limited,
Mandamarri Division,
Mandamarri-504231.

..Respondent.

APPEARANCES

For the Petitioner : NIL

For the Respondent : M/s. P.A.V.V.S. Sarma and Vijaya
Laxmi Panguluri, Advocates**AWARD**

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-22012/311/2005-IR(CM-II) dated 9-10-2006 referred the following dispute between the management of the Singareni Collieries Company Limited and their workman under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is.

SCHEDULE

"Whether the action the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri Koppala Oddehwe, 14-10-2002 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

1. The case is called out several times after repeated interval. None appeared for Petitioner. Respondent's representative present. Petitioner has not submitted his claim statement although several opportunities has been given to him. He is absent today also. No application for adjournment has been filed. As such, it appears that the Petitioner is not interested to pursue this case.

2. Accordingly, this case is being closed and this Court is of the view that the Petitioner deserves no relief in respect of the matter in reference. Hence, 'Nil' Award is passed.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 18th day of August, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for Petitioner	Witnesses examined for Respondent
Nil	Nil

Documents marked for the Petitioner

Nil

Documents marked for the Respondent

Nil.

सं. 1-2006, 4 सितम्बर, 2008

क्र. आ. 2743 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) का प्राव 17 के अनुसार में केन्द्रीय सरकार एम्. सी. पी. एल. के प्रवर्धन के सिद्ध नियोजकों और उनके कार्यस्थलों के बीच अनुव्यय में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिनियम, 1947 के प्राव 17 के अन्तर्गत में, 09-2006 का प्रवर्धन करने के लिए केन्द्रीय सरकार का 04-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[म. सं. 12012/309/2008-IR(CM-II) आई.आर. (संख्या II)]

अजय कुमार गौर, जज, अध्यक्षी

New Delhi, the 1th September, 2008

S.O. 2743. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 69/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Co. Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 04-9-2008.

[No. 1-22012/309/2008-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD**

Present : Shri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer

Dated the 18th day of August, 2008

Industrial Dispute No. 69/2006

BETWEEN

The General Secretary,
(Sri Bandari Satyanarayana)
Singareni Collieries Employees Council,
H.No.18-3-90/3, Ganesh Nagar
Markandeya Colony
Godavarikhani - 505260

..Petitioner

AND

The General Manager,
M/s. Singareni Collieries
Company Limited,
Mandamarri Division,
Mandamarri - 504231

..Respondent

APPEARANCES

For the Petitioner : Nil.

For the Respondent : M/s. P.A.V.V.S. Sarma and Vijaya
Laxmi Panguluri, Advocates

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-22012/309/2005-IR(CM-II) dated 9-10-2006 referred the following dispute between the management of the Singareni Collieries Company Limited and their workman under Section 10(1) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the action the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri K. Srinivas, w.e.f. 29-5-2001 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case is called out several times after repeated intervals. None appeared for Petitioner. Respondent's representative present. Petitioner has not submitted his claim statement although several opportunities has been given to him. He is absent today also. No application for adjournment has been filed. As such, it appears that the Petitioner is not interested to pursue this case.

3. Accordingly, this case is being closed and this Court is of the view that the Petitioner deserves no relief in respect of the matter in reference. Hence, 'Nil' Award is passed.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 18th day of August, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for
Petitioner

NIL

Witnesses examined for
Respondent

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का. आ. 2744.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एस. सी. सी. एल. के प्रबंधन के संबंध विवादों और उनके कर्मचारों के बीच अनुयन्त्र में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद को पंचाट (संदर्भ सं. 68/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 04-9-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/314/2005-आई.आर.(सीएम-1)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2744.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 68/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Co. Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on 04-9-2008.

[No. 1-22012/314/2005-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT HYDERABAD

Present : Shri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer

Dated the 18th day of August, 2008

Industrial Dispute No. 68/2006

BETWEEN

The General Secretary,
(Sri Bandari Satyanarayana)
Singareni Collieries Employees Council,
H.No.18-3-90/3, Ganesh Nagar
Markandeya Colony,
Godavarikhani- 505209

...Petitioner

AND

The General Manager,
M/s. Singareni Collieries
Company Limited,
Mandamarri Division,
Mandamarri - 504231

...Respondent

APPEARANCES

For the Petitioner : NIL

For the Respondent : M/s. P.A.V.V.S. Sama and Vijaya Laxmi Panguluri, Advocates

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-22012/314/2005-IR(CM-II) dated 9-10-2006 referred the following dispute between the management of the Singareni Collieries Company Limited and their workman under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is.

SCHEDULE

"Whether the action the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri Beesaboina Ramulu w.e.f. 22-1-2002 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case is called out several times after repeated intervals. None appeared for Petitioner. Respondent's representative present. Petitioner has not submitted his claim statement although several opportunities has been given to him. He is absent today also. No application for adjournment has been filed. As such, it appears that the Petitioner is not interested to pursue this case.

3. Accordingly, this case is being closed and this Court is of the view that the Petitioner deserves no relief in respect of the matter in reference. Hence, 'NIL' Award is passed.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 18th day of August, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidenceWitnesses examined for
Petitioner

NIL

Witnesses examined for
Respondent

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2008

का. आ. 2745.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एस.

सी. सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके वर्मकरों के बीच अभुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचात (संदर्भ सं. 67/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को (4-9-2008) को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/317/2005-आईआर (सीएस II)]
अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th September, 2008

S.O. 2745,--In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 67/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Co. Ltd., and their workman, which was received by the Central Government on 04-9-2008.

[No. L-22012/317/2005-IR(CM-II)]
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, HYDERABAD

PRESENT : Shri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer

Dated the 18th day of August, 2008

Industrial Dispute No. I. D. 67/2006

BETWEEN

The General Secretary,
(Sri Bandari Satyanarayana)
Singareni Collieries Employees Council,
H No.18-3-90/3, Ganesh Nagar
Markandeya Colony,
Godavari Khani - 505209

Petitioner

AND

The General Manager,
M/s. Singareni Collieries
Company Limited,
Mandamarri Division,
Mandamarri - 504231

Respondent

APPEARANCES

under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal. The reference is.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri Gaddla Poshan w.e.f. 31-7-2001 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case is called out several times after repeated intervals. None appeared for Petitioner. Respondent's representative present. Petitioner has not submitted his claim statement although several opportunities has been given to him. He is absent today also. No application for adjournment has been filed. As such, it appears that the Petitioner is not interested to pursue this case.

3. Accordingly, this case is being closed and this Court is of the view that the Petitioner deserves no relief in respect of the matter in reference. Hence, 'NIL' Award is passed.

Dictated to Smt. P. Purni Gowri, Personal Assistant transcribed by her, corrected and pronounced by me on this the 18th day of August, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for Petitioner	Witnesses examined for Respondent
NIL	NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

बड़े दिवस 17 अगस्त 2008

का. अ. 2746. मध्यम संख्या अजय कुमार गौड़ का दिनांक 28-8-2008 (पूर्वार्ध) का जनरेटिव नमों को अध्यापक अथवा अगले आदेशों तक, जो कि प्रकाशित, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-अध्यक्ष न्यायालय, हैदराबाद के वादग्रस्त अधिकारों के रूप में नियुक्त करते हैं।

[No. L-22012/317/2005-आईआर (सीएस II)]

श्री. अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी